RNI NO. CHHHIN/2022/83778
E-mail: newsroutine6@gmail.com

न्यूज रूटीन

www.newsrourine.in
बढ़ते हुए कदम
वर्ष- 05 अंक -03 मार्च 2026 मूल्य - 35 रु.

संकल्प का बजट

Follow Us :- @newsroutine @newsroutine @newsroutine @newsroutine

"Give To Gain" की भावना के साथ महिला सशक्तिकरण की नई पहचान बना

नम्रता आनन्द डोंगरे, अपर कलेक्टर

श्रीमती अंकिता सोम, सीईओ, जिला पंचायत

श्रीमती रत्ना सिंह, पुलिस अधीक्षक

"Give To Gain" की भावना के साथ महिला सशक्तिकरण की नई पहचान बना जिला एमसीबीअंतरराष्ट्रीय महिला दिवस केवल एक औपचारिक उत्सव नहीं, बल्कि महिलाओं के अधिकार, सम्मान और उनकी उपलब्धियों को पहचान देने का महत्वपूर्ण अवसर है। वर्ष 2026 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की मुख्य वैश्विक अभियान थीम "Give To Gain" (पाने के लिए देना) रखी गई है। इस थीम का मूल संदेश यह है कि जब समाज महिलाओं को शिक्षा, अवसर, संसाधन और सहयोग प्रदान करता है, तो इसका लाभ पूरे समाज और राष्ट्र को मिलता है। महिलाओं को सशक्त बनाना वास्तव में एक समृद्ध और संतुलित समाज की आधारशिला है।

छत्तीसगढ़ में भी महिला सशक्तिकरण को लेकर निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने महिलाओं के सम्मान, स्वावलंबन और सामाजिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्ष 2026 को महतारी गौरव वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। यह निर्णय केवल प्रतीकात्मक नहीं है, बल्कि महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक व्यापक पहल है।

राज्य सरकार की महतारी वंदन योजना के माध्यम से प्रदेश की लगभग 70 लाख महिलाएं आर्थिक सहायता प्राप्त कर रही हैं। इस योजना ने महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ उनमें आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास की भावना को भी मजबूत किया है। इसके अतिरिक्त महिलाओं की सुरक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भी कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) जिला महिला नेतृत्व और उनकी उपलब्धियों

श्रीमती प्रतिमा यादव, अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, मनेंद्रगढ़

के कारण प्रदेश में एक सकारात्मक उदाहरण बनकर उभर रहा है। जिले के जनकपुर क्षेत्र की दर्शना सिंह ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) 2025 में सफलता प्राप्त कर आईपीएस पद के लिए चयनित होकर जिले और प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। उनकी उपलब्धि यह संदेश देती है कि छोटे शहरों और ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाली बेटियां भी अपने परिश्रम और संकल्प के बल पर देश की सर्वोच्च सेवाओं में स्थान प्राप्त कर सकती हैं।

एमसीबी जिले में प्रशासनिक स्तर पर भी महिलाओं की मजबूत भागीदारी देखने को मिलती है। वर्तमान में 20 से अधिक महिलाएं विभिन्न प्रशासनिक पदों पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। जिले की पुलिस अधीक्षक रत्ना सिंह के नेतृत्व में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी अंकिता सोम सहित कई महिला अधिकारी प्रशासनिक व्यवस्था को सशक्त बनाने और विकास कार्यों को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में भी महिलाओं की सक्रिय भागीदारी लोकतंत्र की मजबूती का प्रतीक है। जिला पंचायत अध्यक्ष यशवंती सिंह, जनपद पंचायत खड़गवां की अध्यक्ष श्याम बाई मरकाम, जनपद पंचायत मनेन्द्रगढ़ की जानकीबाई खुसरो, नगर पालिका परिषद मनेन्द्रगढ़ की अध्यक्ष प्रतिमा यादव तथा नगर पंचायत झगराखांड़ की अध्यक्ष ललिता यादव जैसी महिला जनप्रतिनिधि अपने नेतृत्व और समर्पण से जिले के विकास को नई दिशा दे रही हैं। उन्होंने यह सिद्ध किया है कि जब महिलाओं को अवसर मिलता है, तो वे समाज और प्रशासन दोनों स्तरों पर प्रभावी नेतृत्व प्रदान कर सकती हैं। एमसीबी जिले की महिलाएं केवल प्रशासन और राजनीति तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सेवा और आर्थिक गतिविधियों जैसे अनेक क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रही हैं। स्वयं सहायता समूहों, सामाजिक संगठनों और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाएं न केवल अपनी आजीविका सशक्त कर रही हैं, बल्कि समाज में जागरूकता और सामाजिक समरसता को भी बढ़ावा दे रही हैं।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2026 की "Give To Gain" थीम हमें यह याद दिलाती है कि महिलाओं को अवसर, शिक्षा और संसाधन प्रदान करना वास्तव में समाज के समग्र विकास में निवेश करने के समान है। एमसीबी जिले की महिलाएं आज इस सोच को साकार करते हुए यह सिद्ध कर रही हैं कि सशक्त महिला ही सशक्त समाज और सशक्त राष्ट्र की आधारशिला है।

छत्तीसगढ़ के शिमला मैनपाट में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल बनाएगा सर्वसुविधायुक्त पर्यटन-आवासीय परिसर

छत्तीसगढ़ के 'शिमला' नाम से प्रसिद्ध मैनपाट में पर्यटन सुविधाओं और आवासीय विकास को नई गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। राज्य सरकार द्वारा मैनपाट में 4.80 हेक्टर (12 एकड़) भूमि अटल विहार योजना हेतु छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल को आवंटित की गई है।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष श्री अनुराग सिंह देव ने बताया कि इस भूमि पर आधुनिक एवं बहुउपयोगी पर्यटनङ्कआवासीय परिसर का निर्माण शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। प्राकृतिक परिवेश के अनुरूप विकसित होने वाली यह परियोजना मैनपाट आने वाले पर्यटकों को बेहतर, सुरक्षित और किफायती ठहराव उपलब्ध कराएगी।

श्री सिंह देव ने कहा कि यह निर्णय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में, आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी और पर्यटन मंत्री श्री राजेश अग्रवाल के सक्रिय प्रयासों से संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि मैनपाट में लगातार बढ़ते पर्यटक आगमन को देखते हुए इस तरह की सुविधाओं की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी।

प्रस्तावित परिसर में आधुनिक वेलनेस एवं मनोरंजन सुविधाएँ विकसित की जाएंगी। श्री सिंह देव ने बताया कि परियोजना में केरल मॉडल पर आधारित वेलनेस सेंटर, प्राकृतिक पंचकर्म चिकित्सा, हर्बल स्पा और आयुष सेवाएं प्रस्तावित हैं। साथ ही 24म्7 क्लब हाउस, मिलेट्स कैफे, जिम, स्विमिंग पूल, किड्स प्ले एरिया, स्टीम बाथ और एंटरटेनमेंट ज़ोन विकसित किए जाएंगे। पर्यावरण अनुकूल विकास के तहत ट्री हाउस, कॉटेज और स्थानीय जीवन एवं संस्कृति का अनुभव कराने वाला सांस्कृतिक क्षेत्र भी शामिल होगा।

उन्होंने कहा कि परियोजना से मैनपाट में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय रोजगार के अवसर सृजित होंगे और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में नई संभावनाएं खुलेंगी। गुणवत्तापूर्ण आवासीय सुविधा उपलब्ध होने से पर्यटकों का ठहराव समय बढ़ेगा, जो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा।

आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि मैनपाट छत्तीसगढ़ का विशिष्ट एवं उभरता हुआ पर्यटन गंतव्य है। तेजी से बढ़ रही पर्यटक संख्या को देखते हुए यहाँ आधुनिक सुविधाओं का विकास अत्यावश्यक है। हाउसिंग बोर्ड की यह पहल पर्यटन, आवास और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा देगी तथा मैनपाट को राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर सशक्त रूप से स्थापित करेगी।

पर्यटन मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने परियोजना को छत्तीसगढ़ के पर्यटन विस्तार के लिए मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि आधुनिक पर्यटन सुविधाओं के विकास से पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिलेगा और राज्य का हॉस्पिटैलिटी सेक्टर मजबूत होगा।

सीतापुर विधायक श्री रामकुमार टोप्पो ने इसे मैनपाट के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि यह परियोजना स्थानीय युवाओं को रोजगार एवं व्यापार के अवसर उपलब्ध कराएगी और क्षेत्र की पहचान को नई ऊँचाई देगी।

अध्यक्ष श्री अनुराग सिंह देव ने कहा कि यह पहल छत्तीसगढ़ में पर्यटनङ्कआवास विकास के क्षेत्र में गृह निर्माण मंडल की ऐतिहासिक भूमिका को मजबूत करेगी और भविष्य में मैनपाट को एक प्रमुख राष्ट्रीय पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित करने का आधार बनेगी।

अपने अधिकारों को लेकर सजग हों उपभोक्ता

वैसे बाजार में उपभोक्ताओं का शोषण होना कोई नई बात नहीं है बल्कि उपभोक्ताओं के शोषण की जड़ें आज बहुत गहरी हो चुकी हैं।

जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावट, नाप-तोल में गड़बड़ी, मनमाने दाम वसूलना, बगैर मानक वस्तुओं की बिक्री, ठगी, सामान की बिक्री के बाद गारंटी अथवा वारंटी के बावजूद सेवा प्रदान नहीं करना इत्यादि समस्याओं से ग्राहकों का सामना अक्सर होता रहता है। ऐसी ही समस्याओं से उन्हें निजात दिलाने और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। वास्तव में यह उपभोक्ताओं को उनकी शक्तियों और अधिकारों के बारे में जागरूक करने का एक महत्वपूर्व अवसर है।

उपभोक्ता आन्दोलन की नींव सबसे पहले 15 मार्च 1962 को अमेरिका में रखी गई थी और 15 मार्च 1983 से यह दिवस इसी दिन निरन्तर मनाया जा रहा है। भारत में उपभोक्ता आन्दोलन की शुरूआत मुम्बई में वर्ष 1966 में हुई थी। तत्पश्चात् पुणे में वर्ष 1974 में ग्राहक पंचायत की स्थापना के बाद कई राज्यों में उपभोक्ता कल्याण के लिए संस्थाओं का गठन किया गया। इस प्रकार उपभोक्ता हितों के संरक्षण की दिशा में यह आन्दोलन आगे बढ़ता गया।

वैसे बाजार में उपभोक्ताओं का शोषण होना कोई नई बात नहीं है बल्कि उपभोक्ताओं के शोषण की जड़ें आज बहुत गहरी हो चुकी हैं। उपभोक्ताओं को इस शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए कई कानून भी बनाए गए लेकिन जब से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अस्तित्व में आने के बाद से उपभोक्ताओं को शीघ्र, त्वरित एवं कम खर्च पर न्याय दिलाने का मार्ग प्रशस्त हुआ और उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की सेवाएं प्रदान करने वाली कम्पनियां व प्रतिष्ठान अपनी सेवाओं अथवा उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार के प्रति सचेत हुए।

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाए जाने का मूल उद्देश्य यही है कि उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाए और अगर वे धोखाधड़ी, कालाबाजारी, घटतौली इत्यादि के शिकार होते हैं तो वे इसकी शिकायत उपभोक्ता अदालत में कर सकें। ग्राहकों के साथ आए दिन होने वाली धोखाधड़ी को रोकने और उपभोक्ता अधिकारों को ज्यादा मजबूती प्रदान करने के लिए देश में 20 जुलाई 2020 को 'उपभोक्ता संरक्षण कानून-2019' (कन्ज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट-2019) लागू किया गया, जिसमें उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की ठगी और धोखाधड़ी से बचाने के लिए कई प्रावधान हैं। यह कानून अब साढ़े तीन दशक पुराने 'उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986' का स्थान ले चुका है।

भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून में स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक वह व्यक्ति उपभोक्ता है, जिसने किसी वस्तु या सेवा के क्रय के बदले धन का भुगतान किया है या भुगतान करने का आश्वासन दिया है और ऐसे में किसी भी प्रकार के शोषण अथवा उत्पीड़न के खिलाफ वह अपनी आवाज उठा सकता है तथा क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता है। खरीदी गई किसी वस्तु, उत्पाद अथवा सेवा में कमी या उसके कारण होने वाली किसी भी प्रकार की हानि के बदले उपभोक्ताओं को मिला कानूनी संरक्षण ही उपभोक्ता अधिकार है। यदि खरीदी गई किसी वस्तु या सेवा में कोई कमी है या उससे आपको कोई नुकसान हुआ है तो आप उपभोक्ता फोरम में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

उपभोक्ताओं का शोषण होने और ऐसे मामलों में उनके द्वारा उपभोक्ता अदालत की शरण लिए जाने के बाद मिले न्याय के कुछ मामलों पर नजर डालें तो स्पष्ट हो जाता है कि उपभोक्ता अदालतें उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए कितना बड़ा काम कर रही हैं। एक उपभोक्ता ने एक दुकान से बिजली का एक पंखा खरीदा लेकिन एक वर्ष की गारंटी होने के बावजूद थोड़े ही समय बाद पंखा खराब होने पर भी जब दुकानदार उसे ठीक कराने या बदलने में आनाकानी करने लगा तो उपभोक्ता ने उपभोक्ता अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने अपने आदेश में नया पंखा देने के साथ उपभोक्ता को हर्जाना देने का भी फरमान सुनाया।

एक अन्य मामले में एक आवेदक ने सरकारी नौकरी के लिए अपना आवेदन अंतिम तिथि से पांच दिन पूर्व ही स्पीड पोस्ट द्वारा संबंधित विभाग को भेज दिया लेकिन आवेदन निर्धारित तिथि तक नहीं पहुंचने के कारण उसे परीक्षा में बैठने का अवसर नहीं दिया गया। आवेदक ने डाक विभाग की लापरवाही को लेकर उपभोक्ता अदालत का दरवाजा खटखटाया और उसे न्याय मिला। चूंकि स्पीड पोस्ट को डाक अधिनियम में एक आवश्यक सेवा माना गया है, इसलिए उपभोक्ता अदालत ने डाक विभाग को सेवा शर्तों में कमी का दोषी पाते हुए डाक विभाग को मुआवजे के तौर पर आवेदक को एक हजार रुपये की राशि देने का आदेश दिया।

ऐसी ही छोटी-बड़ी समस्याओं का सामना जीवन में कभी न कभी हम सभी को करना ही पड़ता है लेकिन अधिकांश लोग अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ते। इसका एक प्रमुख कारण यही है कि देश की बहुत बड़ी आबादी अशिक्षित है, जो अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति अनभिज्ञ है लेकिन जब शिक्षित लोग भी अपने उपभोक्ता अधिकारों के प्रति उदासीन नजर आते हैं तो आश्चर्य होता है। यदि आप एक उपभोक्ता हैं और किसी भी प्रकार के शोषण के शिकार हुए हैं तो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़कर न्याय पा सकते हैं। कोई वस्तु अथवा सेवा लेते समय हम धन का भुगतान तो करते हैं पर बदले में उसकी रसीद नहीं लेते। शोषण से मुक्ति पाने के लिए सबसे जरूरी है कि आप जो भी वस्तु, सेवा अथवा उत्पाद खरीदें, उसकी रसीद अवश्य लें। यदि आपके पास रसीद के तौर पर कोई सबूत ही नहीं है तो आप अपने मामले की पैरवी सही ढ़ंग से नहीं कर पाएंगे।

पिछले कुछ वर्षों में ऐसे अनेक मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें उपभोक्ता अदालतों से उपभोक्ताओं को पूरा न्याय मिला है लेकिन आपसे यह अपेक्षा तो होती ही है कि आप अपनी बात अथवा दावे के समर्थन में पर्याप्त सबूत तो पेश करें। उपभोक्ता अदालतों की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इनमें लंबी-चौड़ी अदालती कार्यवाही में पड़े बिना आसानी से शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। यही नहीं, उपभोक्ता अदालतों से न्याय पाने के लिए न तो किसी प्रकार के अदालती शुल्क की आवश्यकता पड़ती है और मामलों का निपटारा भी शीघ्र होता है।

न्यूज रूटीन

बढ़ते हुए कदम

● वर्ष: 05 ● अंक:03 ● मार्च 2026

RNI NO. CHHHIN/2022/83778

E-mail: newsroutine6@gmail.com

सारंगढ़-बिलाईगढ़

प्रधान संपादक

गुलाब दास दीवान

सहसंपादक

प्रवीण खरे

कानूनी सलाहकार

जवाहर पड़वार

इंदुभूषण पड़वार

प्रधान कार्यालय

न्यूज रूटीन

बाजार काम्पलेक्स, नगर पंचायत पवनी,
जिला- सारंगढ़ बिलाईगढ़
पिन. नं. 493338
मो.नं. 9294743139

रायपुर कार्यालय

फ्लैट नं. 109, सी ब्लाक, कमल हाईट्स,
सेक्टर-4, कमल विहार, रायपुर (छ.ग.)
पिन नं. 492004
मो. नं. 6261155546

न्यूज रूटीन में प्रकाशित आलेखों से संपादक, प्रकाशक, मुद्रक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है। विवादग्रस्त न्यायिक प्रकरणों का कार्यक्षेत्र सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला रहेगा। सभी पद पूर्णत: मानसेवी व अवैतनिक। समाचार स्त्रोत हमारे सभी संवाददाता/प्रतिनिधि। संदर्भ सामग्री: इंटरनेट, प्रमुख समाचार पत्र एवं नामचीन पत्रिकाओं से सादर साभार।

संपादक- गुलाब दास दीवान

अंदर के पृष्ठों में

5 सुशासन, विकास और सुरक्षा के संकल्प के साथ बढ़ रहे हैं आगे

21 ईरान पर हमले से बढ़ी वैश्विक अनिश्चितता

- 'संकल्प से सिद्धि' का रोडमैप 10
- जन्मदिन पर मुख्यमंत्री निवास बना उल्लास का केंद्र 14
- महिला सशक्तिकरण के नवयुग की ओर अग्रसर छत्तीसगढ़ 16
- टी-20 विश्व कप में भारतीय क्रिकेट का स्वर्णकाल 18
- नीतीश कुमार की नई सधी हुई बिहारी चाल 24
- रायपुर में गूंजा राष्ट्रभक्ति और नारी शक्ति का संदेश 26
- खतरनाक है खेतों से पेड़ों का उजड़ना 29
- अपने अधिकारों को लेकर सजग हों उपभोक्ता 30

बस्तर से वैश्विक मंच तक छत्तीसगढ़ पर्यटन की नई उड़ान 28

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक- गुलाब दास दीवान, द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि. (छ.ग.) भवन, प्रेस काम्पलेक्स रजबंधा मैदान रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित एवं ग्राम-पोस्ट-पवनी, तहसील-बिलाईगढ़, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.), 493338 से प्रकाशित। RNI NO. CHHHIN/2022/83778 सम्पादक- गुलाब दास दीवान, मो. 9294743139

ईरान युद्ध 'चूल्हे' तक

ईरान युद्ध का असर हमारी रसोई और चूल्हे तक आ जाएगा, यह आकलन करने में केंद्रीय कैबिनेट ने 11 दिन खपा दिए। अंतत- कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी को ऐसे निर्देश देने पड़े कि सभी मंत्रालय आपस में मिल कर काम करें। संभावित चुनौतियों के लिए तैयार रहें। देशवासियों पर युद्ध का असर कम पड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री ने 'चुनौती' की बात स्वीकार की है और 'चाहिए' शब्द का इस्तेमाल कर उपदेश दिया है। यह क्यों नहीं हो सकता कि खुद प्रधानमंत्री मंत्रियों के स्तर पर समन्वय करें। चूंकि वह देश के सर्वोच्च, संवैधानिक कार्यकारी प्रमुख हैं, लिहाजा उन्हें देश को संबोधित कर हकीकत बयां करनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने नोटबंदी, कोरोना वैश्विक महामारी, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कई बार राष्ट्र को संबोधित किया है। देशवासियों ने उन्हें भरपूर समर्थन और सहयोग भी दिया है। बहरहाल भारत में करीब 19.5 करोड़ घन मीटर गैस की खपत औसतन हर रोज होती है, जबकि गैस का घरेलू उत्पादन करीब 10 करोड़ घन मीटर ही है, जाहिर है कि भारत को गैस आयात करनी पड़ती है। इसमें रसोई गैस एलपीजी के अलावा, एलएनजी, पीएनजी, सीएनजी भी हमारी जिंदगी की सक्रियता के लिए बेहद अनिवार्य हैं। उनके बिना जिंदगी, समाज और कारोबार का चक्का ही जाम हो जाएगा। पीएनजी पाइपलाइन के जरिए हमारे घरों तक जाती है और 1.62 करोड़ इसके कनेक्शन हैं। एलपीजी के 33 करोड़ से अधिक उपभोक्ता हैं। सीएनजी वाहनों में इस्तेमाल की जाती है। एलएनजी खाद के प्लांट से लेकर औद्योगिक उत्पादन, विनिर्माण की इकाइयों के लिए 'संजीवनी' है। प्रधानमंत्री मोदी देश को संबोधित कर खुलासा कर सकते हैं कि भारत ने अमरीका के साथ 22 लाख टन गैस का सौदा किस आधार पर किया है? इसके अलावा, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नॉर्वे, पश्चिम अफ्रीका, नाइजीरिया, अंगोला और अल्जीरिया सरीखे देशों से पर्याप्त गैस की आपूर्ति का अपडेट क्या है?

ये छोटे, पिद्दी से देश भारत जैसे विराट, विशाल देश को गैस सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन खुद 78 साल का भारत अपने लिए गैस का पर्याप्त उत्पादन करने में सक्षम क्यों नहीं हो सका? यह वाकई यक्ष-प्रश्न है। गैस की जानकारी देश को देने में गोपनीयता क्या है? कूटनीतिक रणनीति क्या है? आपकी तेल-गैस की सप्लाई को कौन 'तारपीडो' करेगा? यह तो आम भारतवासी की जिंदगी और चूल्हे से जुड़ा संवेदनशील विषय है। आखिर प्रधानमंत्री आपदा या संकट के दौर में देश की जनता, विपक्ष और मीडिया को खुलासा क्यों नहीं करेंगे? ऊर्जा-संकट से ही हमारी खाद्य-सुरक्षा प्रत्यक्ष तौर पर जुड़ी है। ठीक है, केंद्र सरकार ने 'आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955' की अधिसूचना जारी कर उसे लागू कर दिया है, लेकिन आम आदमी सडक़ पर उतरने को विवश है। गैस सिलेंडर लेकर लोगों ने उसी तरह कतारें लगाना शुरू कर दिया है, जिस तरह कोरोना महामारी के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर हुआ था। वह संकट भी फर्जी था, चिंता और अफवाहें ज्यादा थीं। मौजूदा संकट आम रसोई के मद्देनजर है कि शाम को गैस का चूल्हा जलेगा या नहीं, घर का खाना बनेगा अथवा नहीं। यह संकट उस वर्ग का ज्यादा है, जिसकी जिंदगी धक्के खाने में खप जाती है, जिसके संसाधन बेहद सीमित हैं और जिसने जनादेश देकर नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है। क्या प्रधानमंत्री उन लोगों को भी संबोधित नहीं कर सकते? इस संकट के दरमियान ही अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान आया है कि युद्ध का काम लगभग पूरा हो चुका है। अर्थात अमरीका युद्ध को समाप्त करने और निकलने का सुरक्षित रास्ता तलाश रहा है, लेकिन इजरायल और ईरान फिलहाल ऐसा नहीं सोच रहे, जाहिर है कि तेल-गैस का संकट बरकरार रहेगा, बल्कि बढ़ भी सकता है। करीब 60 देशों में पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ चुकी हैं। बहरहाल रूस हमारे लिए चमकती हुई उम्मीद है। वह गैस का सबसे बड़ा निर्यातक देश है और कच्चे तेल का भी दूसरा सबसे बड़ा देश है। अमरीका ने रूस पर से तेल-गैस संबंधी पाबंदियां हटा ली हैं। रूस ने हमें कच्चा तेल और गैस की आपूर्ति शुरू भी कर दी है। करीब 95 लाख बैरल तेल भारतीय तट पर मौजूद है।

पीएनजी पाइपलाइन के जरिए हमारे घरों तक जाती है और 1.62 करोड़ इसके कनेक्शन हैं। एलपीजी के 33 करोड़ से अधिक उपभोक्ता हैं। सीएनजी वाहनों में इस्तेमाल की जाती है।

संपादक

खतरनाक है खेतों से पेड़ों का उजड़ना

न तो अब खेतों में कोयल की कूक सुनाई देती है और न ही सावन के झूले पड़ते हैं. यदि फसल को किसी आपदा का ग्रहण लग जाए, तो अतिरिक्त आय का जरिया होने वाले फल भी गायब हैं. अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रिका 'नेचर सस्टैनबिलिटी' में हाल में प्रकाशित आलेख बताता है कि भारत में खेतों में पेड़ लगाने की परंपरा समाप्त हो रही है.

कृषि-वानिकी का मेलजोल कभी भारत के किसानों की ताकत था. कई पर्व-त्योहार, लोकाचार, गीत-संगीत खेतों में खड़े पेड़ों के इर्द गिर्द रहे हैं. मार्टिन ब्रांट ?, दिमित्री गोमिंस्की, फ्लोरियन रेनर, अंकित करिरिया ?, वेंकन्ना बाबू गुथुला, फिलिप सियाइस ?, जियाओये टोंग ?, वेनमिन झांग ?, धनपाल गोविंदराजुलु ?, डैनियल ऑर्टिज-गोंजालो और राससम फेंशोल्टन के बड़े दल ने भारत के विभिन्न हिस्सों में जाकर पाया कि अब खेत किनारे छाया मिलना मुश्किल है.

इसके कई विषम परिणाम खेत झेल रहा है. जब बढ़ता तापमान गंभीर समस्या के रूप में सामने है और सभी जानते हैं कि धरती पर अधिक से अधिक हरियाली की छतरी ही इससे बचाव का जरिया है, ऐसे में यह शोध गंभीर चेतावनी है कि बीते पांच वर्षों में हमारे खेतों से 53 लाख फलदार

साल 2010-11 में दर्ज किये गये पेड़ों में से करीब 11 फीसदी बड़े छायादार पेड़ 2018 तक गायब हो चुके थे. बहुत जगहों पर तो खेतों में मौजूद आधे पेड़ गायब हो चुके हैं.

व छायादार पेड़ गायब हो गये हैं. इनमें नीम, जामुन, महुआ और कटहल जैसे पेड़ प्रमुख हैं. इन शोधकर्ताओं ने भारत के खेतों में मौजूद 60 करोड़ पेड़ों का नक्शा तैयार किया और लगातार दस साल उनकी निगरानी की.

कोपेनहेगन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के अध्ययन के अनुसार, देश में प्रति हेक्टेयर पेड़ों की औसत संख्या 0.6 दर्ज की गयी. इनका सबसे ज्यादा घनत्व उत्तर-पश्चिमी भारत में राजस्थान और दक्षिण-मध्य क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में दर्ज किया गया है. यहां पेड़ों की मौजूदगी प्रति हेक्टेयर 22 तक दर्ज की गयी. रिपोर्ट बताती है कि खेतों में सबसे अधिक पेड़ उजाड़ना में तेलंगाना और महाराष्ट्र अव्वल रहे हैं. इससे खेत तो कम होंगे ही, लेकिन पेड़ों का कम होना मानवीय अस्तित्व पर बड़े संकट का आमंत्रण है. आज समय की मांग है कि खेतों के आसपास सामुदायिक वानिकी को विकसित किया जाए, जिससे जमीन की उर्वरा, धरती की कोख का पानी और हरियाली का साया बना रहे.

साल 2010-11 में दर्ज किये गये पेड़ों में से करीब 11 फीसदी बड़े छायादार पेड़ 2018 तक गायब हो चुके थे. बहुत जगहों पर तो खेतों में मौजूद आधे पेड़ गायब हो चुके हैं. यह भी पता चला है कि 2018 से 2022 के बीच करीब 53 लाख पेड़ खेतों से अदृश्य थे, यानी इस दौरान हर किलोमीटर क्षेत्र से औसतन 2.7 पेड़ नदारद मिले. वहीं कुछ क्षेत्रों में तो हर किलोमीटर क्षेत्र से 50 तक पेड़ गायब हो चुके हैं.

यह विचार करना होगा कि आखिर किसान ने अपने खेतों से पेड़ों को उजाड़ा क्यों? किसान भलीभांति यह जानता है कि खेत पर छायादार पेड़ होने का अर्थ है पानी संचयन, पत्ते और पंछियों की बीट से निशुल्क कीमती खाद, मिट्टी के मजबूत पकड़ और सबसे बड़ी बात- खेत में हर समय किसी बड़े-बूढ़े के बने रहने का एहसास. इन पेड़ों पर बसेरा करने वाले पक्षी कीट-पतंगों से फसलों की रक्षा करते थे. फसलों को नुकसान करने वाले कीट सबसे पहले मेड़ के पेड़ पर ही बैठते हैं. उन पेड़ों पर दवाओं को छिड़काव कर दिया जाए, तो फसलों पर छिड़काव करने से बचत हो सकती है. जलावन, फल-फूल से अतिरिक्त आय तो है ही.

फिर भी नीम, महुआ, जामुन, कटहल, खेजड़ी (शमी), बबूल, शीशम, करोई, नारियल आदि जैसे बहुउद्देशीय पेड़ों का काटा जाना, जिनका मुकुट 67 वर्ग मीटर या उससे अधिक था, किसान की किसी बड़ी मजबूरी की तरफ इशारा करता है. यह भी है कि खेती का रकबा तेजी से कम होता जा रहा है. एक तो जमीन का बंटवारा हुआ, फिर लोगों ने व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए खेतों को बेचा.

साल 1970-71 तक देश के आधे किसान सीमांत थे, यानी उनके पास एक हेक्टेयर या उससे कम जमीन थी. साल 2015-16 आते-आते सीमांत किसान बढ़कर 68 प्रतिशत हो गये हैं. अनुमान है कि आज इनकी संख्या 75 फीसदी है. सरकारी आंकड़ा कहता है कि सीमांत किसानों की औसत खेती 0.4 हेक्टेयर से घटकर 0.38 हेक्टेयर रह गयी है. ऐसा ही छोटे, अर्ध मध्यम और मझोले किसान के साथ हुआ. कम जोत का सीधा असर किसानों की आय पर पड़ा है. अब वह जमीन के छोटे से टुकड़े पर अधिक कमाई चाहता है, तो उसने पहले खेत की चौड़ी मेढ़ को ही तोड़ डाला. इसके चलते वहां लगे पेड़ कटे. उसे लगा कि पेड़ के कारण हल चलाने लायक भूमि और सिकुड़ रही है, तो उसने पेड़ पर कुल्हाड़ी चला दी.

बस्तर से वैश्विक मंच तक छत्तीसगढ़ पर्यटन की नई उड़ान

अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ किर्सी ह्यवैरिनेन के प्रवास से छत्तीसगढ़ पर्यटन को नई दिशा

छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल में इन दिनों पर्यटन विकास की एक नई और सकारात्मक इबारत लिखी जा रही है। संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ और हिवा कोचिंग एंड कंसल्टिंग की संस्थापक सुश्री किर्सी ह्यवैरिनेन के छह दिवसीय प्रवास ने राज्य के पर्यटन क्षेत्र को राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण गति प्रदान की है। उनका यह दौरा केवल औपचारिक भ्रमण नहीं, बल्कि स्थानीय समुदाय आधारित सतत पर्यटन मॉडल को वैश्विक मानकों से जोड़ने की ठोस रणनीतिक पहल के रूप में देखा जा रहा है।

दौरे के दूसरे दिन सुश्री किर्सी बस्तर जिले के ग्राम धुड़मारास पहुंचीं, जहां धुरवा डेरा होमस्टे में उनका पारंपरिक ढंग से स्वागत किया गया। सिहाड़ी और महुए की माला पहनाकर तथा धुरवा नृत्य और स्वागत गीतों के माध्यम से ग्रामीणों ने अपनी संस्कृति की जीवंत झलक प्रस्तुत की। आत्मीय स्वागत से अभिभूत सुश्री किर्सी ने कहा कि इस प्रकार का अनुभव उनके लिए अत्यंत विशेष और अविस्मरणीय है। यह स्वागत केवल सांस्कृतिक प्रदर्शन नहीं, बल्कि बस्तर की सामाजिक एकजुटता और आत्मीयता का सशक्त परिचय था।

प्रवास के दौरान उन्होंने बस्तर के पारंपरिक एवं जैविक व्यंजनों का स्वाद भी लिया। कलम भाजी, सेमी और बोदई की सब्जी, केले की सब्जी, उड़द दाल, इमली की चटनी, कोसरा भात तथा मंडिया पेज जैसे स्थानीय व्यंजनों से सजी थाली ने उन्हें यहां की जीवनशैली और खाद्य परंपरा से परिचित कराया। वैश्विक पर्यटन परिदृश्य में स्थानीय खान-पान एक प्रमुख आकर्षण बन चुका है और बस्तर की जैव विविधता आधारित खाद्य संस्कृति विदेशी पर्यटकों के लिए विशिष्ट पहचान बना सकती है।

यह प्रवास विशेष रूप से यूनाइटेड नेशन से जुड़े 'बेस्ट टूरिज्म विलेज अपग्रेड प्रोग्राम' के मानकों के अनुरूप धुड़मारास और आसपास के क्षेत्रों को विकसित करने पर केंद्रित है। सुश्री किर्सी धुरवा डेरा होमस्टे में रहकर स्थानीय समुदाय, स्वयं सहायता समूहों, युवाओं और पर्यटन हितधारकों से संवाद कर सेवा गुणवत्ता, स्वच्छता प्रबंधन, डिजिटल प्रचार, ब्रांडिंग और होमस्टे संचालन के अंतरराष्ट्रीय मानकों पर मार्गदर्शन दे रही हैं। यह भ्रमण जिला प्रशासन तथा छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के समन्वय से आयोजित किया गया है।

प्रवास के दौरान उन्होंने विश्वप्रसिद्ध चित्रकोट जलप्रपात में नौका विहार कर वहां की पर्यटन संभावनाओं का अवलोकन किया और मेंदरी घूमर क्षेत्र में स्थानीय हितग्राहियों के साथ पर्यटन गतिविधियों को विस्तार देने पर चर्चा की। चित्रकोट जलप्रपात पहले से ही राष्ट्रीय स्तर पर पहचान रखता है, किंतु अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ की उपस्थिति इसे वैश्विक प्रचार अभियानों से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण अवसर प्रदान कर सकती है।

सुश्री किर्सी ह्यवैरिनेन के छह दिवसीय प्रवास का प्रभाव बहुआयामी होगा। एक ओर यह बस्तर को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने में सहायक सिद्ध हो सकता है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय युवाओं और महिलाओं के लिए स्वरोजगार के स्थायी अवसर भी सृजित करेगा। सामुदायिक पर्यटन को संस्थागत आधार मिलने से आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी और सतत विकास की अवधारणा को बल मिलेगा।

कभी नक्सल प्रभाव की पहचान से जुड़े रहे बस्तर की छवि अब प्रकृति, संस्कृति और सामुदायिक समृद्धि के मॉडल के रूप में उभर रही है। यदि धुड़मारास 'यूएन बेस्ट टूरिज्म विलेज' मानकों पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ता है, तो यह मॉडल देश के अन्य ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है। सुश्री किर्सी ह्यवैरिनेन का यह प्रवास छत्तीसगढ़ के पर्यटन इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में दर्ज होने की संभावना रखता है, जो राज्य की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच तक पहुंचाने की दिशा में निर्णायक कदम साबित होगा।

सुशासन, विकास और सुरक्षा के संकल्प के साथ बढ़ रहे हैं आगे

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा

- राज्य के तेज विकास, भ्रष्टाचार पर सख्ती और नक्सलवाद के अंत का संकल्प
- जी राम जी योजना' में मिलेगा 125 दिन का रोजगार
- पीएम आवास योजना में सिर्फ 10 महीनों में 5 लाख से अधिक आवासों का निर्माण
- सिंचाई सुविधा के लिए दो वर्षों में 10 हजार 700 करोड़ रुपये स्वीकृत

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कहा कि राज्य सरकार सुशासन, विकास और सुरक्षा के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने भ्रष्टाचार पर कड़े प्रहार किए हैं और इसमें लिप्त कई लोग आज जेल के पीछे हैं। उन्होंने कहा कि 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के अंतर्गत 7 करोड़ पेड़ लगाए गए हैं तथा उद्योग नीति के तहत काटे जाने वाले पेड़ों की भरपाई भी बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण से की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि भारतीय वन संरक्षण देहरादून द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में वन एवं वृक्ष आवरण में 683 वर्ग किमी की वृद्धि दर्ज की गई है। यह उपलब्धि राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण एवं गर्व का विषय है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ सरकार निर्णायक लड़ाई लड़ रही है और उम्मीद जताई कि 31 मार्च तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का समूल उन्मूलन कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्व में जहां स्कूलों को जला दिया गया था और हथियारों की फैक्ट्रियां संचालित हो रही थीं, वहीं आज बस्तर में विकास की नई धारा बह रही है। स्कूल संचालित हो रहे हैं, अस्पताल खुल रहे हैं और लोगों का समुचित इलाज हो रहा है। पुनर्वास नीति के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं और बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केरल से बड़ा राज्य होने के बावजूद पूर्व में अपेक्षित विकास नहीं हुआ, लेकिन अब प्रदेश में बुनियादी सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। बस्तर पंडुम में इस वर्ष 54 हजार कलाकारों ने पंजीयन कराया है, जो सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक है। होमस्टे को बढ़ावा दिया जा रहा है जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य में विगत दो वर्षों में वन संरक्षण अधिनियम के तहत स्वीकृत खनन प्रकरणों में खनन कार्य हेतु एक लाख 3 हजार 855 पेड़ों की कटाई की गई है, जबकि इसके एवज में खनन एवं औद्योगिक क्षेत्रों में 30 लाख से अधिक पौधे लगाए गए हैं। हमने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत दो वर्षों में करीब 7 करोड़ पेड़ लगाये हैं।

नया रायपुर स्थित ट्राइबल म्यूजियम चर्चा

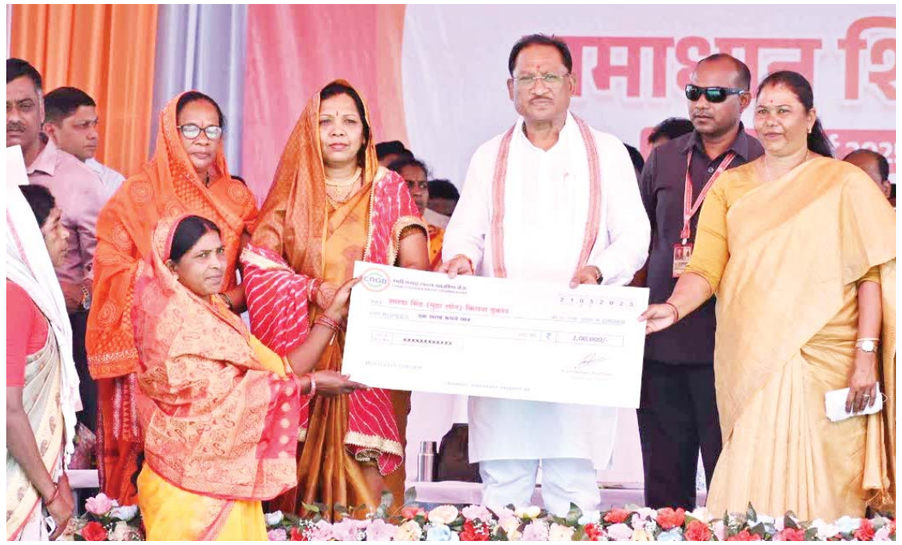

करते हुए उन्होंने कहा कि वहां हजारों पर्यटक पहुंच रहे है और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने भी इसकी प्रशंसा की है। उन्होंने बताया कि प्रदेशवासियों को रामलला के दर्शन कराने के लिए रामलला दर्शन योजना प्रारंभ की गई है, जिसका 42 हजार लोग लाभ उठा चुके हैं। मुख्यमंत्री दर्शन योजना से भी 5 हजार से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं। चरण पादुका योजना को पुन: प्रारंभ किया गया है, जिसे पिछली सरकार ने बंद कर दिया था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 10 महीनों में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 5 लाख से अधिक आवास पूर्ण किए गए हैं, जो देश में सर्वाधिक है। किसानों से 21 क्विंटल तक 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी गई है और अंतर की राशि होली से पहले किसानों को प्रदान कर दी जाएगी। सिंचाई क्षेत्र में जहां पूर्व सरकार ने 5700 करोड़ रुपये स्वीकृत किए थे, वहीं वर्तमान सरकार ने 10700 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 32 हजार पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है और इसे सुव्यवस्थित करने के लिए नया अधिनियम लाया जाएगा। नया रायपुर में 'अंतरिक्ष संगवारी' का उद्घाटन भी किया गया है। शासकीय कर्मचारियों को कैशलैस इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि रेलवे सेक्टर में 47 हजार करोड़ रुपये से अधिक के कार्य प्रगति पर हैं। 'जी राम जी योजना' को मनरेगा से बेहतर बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें 100 के स्थान पर 125 दिनों का रोजगार दिया जाएगा। सरकार की मंशा हाफ बिजली बिल से आगे बढ़कर मुफ्त बिजली बिल की दिशा में जाने की है, जिसके लिए सोलर पैनल स्थापना पर सब्सिडी दी जा रही है। राज्य के 8 नगर निगमों में छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण (सीबीडीए) के माध्यम से गेल और बीपीसीएल द्वारा बायोसीएनजी संयंत्रों की स्थापना की जा रही है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमने सुशासन एवं अभिसरण के रूप में एक नया विभाग ही बना दिया। इसका काम प्रचलित तरीकों से इतर नई सोच के साथ आगे बढ़ना है जिसमें तकनीक का समावेश हो, गवर्नेंस की सर्वोत्तम पद्धतियां जिसमें शामिल हो। हमने ई-आफिस प्रणाली लागू की है, फाइलें अब कंप्यूटर के जरिए बढ़ती हैं, तय समय सीमा में अधिकारियों को अपने अभिमत लिखने होते हैं और आगे फारवर्ड करना होता है। इससे न केवल पारदर्शिता आई है अपितु समय भी बच रहा है। इस प्रणाली को हम राज्य स्तर से जिला स्तर की ओर भी ले जा रहे हैं। हम डिजिटल गवर्नेंस को सभी विभागों में लागू कर रहे हैं, ताकि काम त्वरित गति से हों और लोगों को भटकना न पड़े।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम हाफ बिजली से मुफ्त बिजली की दिशा में बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री सौर घर मुफ्त बिजली योजना ग्रीन एनर्जी को लेकर प्रधानमंत्री जी की सार्थक पहल है। हमने छत्तीसगढ़ में अब तक 27 हजार से अधिक घरों को सौर ऊर्जा से रौशन कर दिया है। केंद्र से उपभोक्ताओं को अनुदान लाभ तो मिलता ही है, हम राज्य में भी उपभोक्ताओं को अनुदान लाभ दे रहे हैं। मैं प्रदेश के सभी नागरिकों से अपील करता हूँ कि प्रधानमंत्री सौर घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ लें और अगले 25 सालों तक मुफ्त बिजली का लाभ लें।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि रेल यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने अमृत स्टेशन योजना के तहत प्रदेश के 32 रेलवे स्टेशनों को आधुनिकीकरण किया जा रहा है। जिसमें 05 स्टेशनों का कार्य पूरा हो चुका है। वंदेभारत एक्सप्रेस की सुविधा नागपुर और विशाखापट्नम के लिए आरंभ की गई है। प्रदेश में 51 हजार करोड़ रूपए की लागत से रेल परियोजनाओं पर काम हो रहा है। रावघाट-जगदलपुर, खरसिया-परमालकसा जैसी महत्वपूर्ण रेल लाइनों के निर्माण से प्रदेश के विकास को तीव्र गति मिलेगी। आज के समय सड़कें जितनी जरूरी हैं उतनी ही जरूरी संचार कनेक्टिविटी भी है, हमारी सरकार ने 500 नये मोबाइल टावर स्वीकृत किये हैं जिससे कनेक्टिविटी की स्थिति और बेहतर होगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में गुणवत्ता की वृद्धि के लिए हम प्रदेश में 5 नये मेडिकल कालेज आरंभ कर रहे हैं। इसमें मनेंद्रगढ़, कबीरधाम, जांजगीर-चांपा एवं दंतेवाड़ा जिला में भूमिपूजन हो चुका है और कुनकुरी में भूमि आवंटन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। अटल जी की संकल्पना एम्स में अब रोबोटिक सर्जरी शुरू हो गई है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत के रूप में देश में हेल्थ केयर का सबसे बड़ा प्लान दिया। इस योजना के माध्यम से 4 हजार 551 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। प्रधानमंत्री जी ने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी बनाये। इसकी शुरूआत भी छत्तीसगढ़ से हुई। हमने युक्तियुक्तकरण के रूप में किया। पिछली सरकार के समय दूरस्थ ग्रामीण स्कूल तो पूरी तरह से शिक्षकविहीन हो गये थे। जिन स्कूलों में शिक्षक थे भी तो वहां भी सामान्यत: प्रति सौ छात्र केवल एक शिक्षक थे। अधिकांश शिक्षक शहरी स्कूलों में आ गये थे, कुछ शहरी स्कूलों में यह अनुपात दस छात्र के पीछे एक शिक्षक का भी था। हमने इस समस्या का निराकरण युक्तियुक्तकरण के माध्यम से निकाला। अब ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में भी शिक्षकों की पदस्थापना कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि भारत के युवा दुनिया भर में कमाल कर रहे हैं। पिछले साल मैं जापान की राजधानी टोक्यो में बस्तर के एक युवा अविनाश तिवारी से मिला। अविनाश वहां एक प्रतिष्ठित कंपनी में कार्य कर करता है। उगते सूरज के देश में छत्तीसगढ़ की प्रतिभा का उजाला देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। हमारी युवा शक्ति हमारी सबसे बड़ी ताकत है। प्रशासनिक प्रणाली बेहतर तरीके से चले और इसमें युवा ऊर्जा का अधिकतम उपयोग हो, इसलिए हम 32 हजार से अधिक पदों पर भर्ती कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा राज्य सरकार का उद्देश्य छत्तीसगढ़ को विकास, सुरक्षा और सुशासन के नए शिखर पर पहुंचाना है।

पुनर्वास नीति से बदली तकदीर, बदली तस्वीर

कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने पुनर्वास केंद्र में वितरित किए 5जी स्मार्टफोन एवं मेसन किट

छत्तीसगढ़ शासन की मानवीय, संवेदनशील एवं दूरदर्शी पुनर्वास नीति नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन की नई इबारत लिख रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के मंशा अनुरूप जिला प्रशासन सुकमा द्वारा आत्मसमर्पित माओवादियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सतत पहल की जा रही है।

जिला मुख्यालय सुकमा स्थित नक्सल पुनर्वास केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में 70 आत्मसमर्पित युवाओं को अत्याधुनिक 5जी स्मार्टफोन तथा 31 युवाओं को रोजगारोन्मुख मेसन (राजमिस्त्री) किट वितरित की गई। कार्यक्रम कलेक्टर श्री अमित कुमार, पुलिस अधीक्षक श्री किरण चव्हाण एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री मुकुंद ठाकुर के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। इस अवसर पर अधिकारियों ने पुनर्वासित युवाओं से आत्मीय संवाद स्थापित कर उनका उत्साहवर्धन किया।

जिला प्रशासन का कहना है कि पुनर्वास केवल आत्मसमर्पण तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भरता, सम्मानजनक जीवन और स्थायी आजीविका से जुड़ा समग्र प्रयास है। इसी सोच के अनुरूप 70 युवाओं को सैमसंग गैलेक्सी 5जी स्मार्टफोन प्रदान किए गए। 50 मेगापिक्सल डुअल कैमरा एवं 5000 मेगाहर्ज फास्ट चार्जिंग बैटरी जैसी आधुनिक सुविधाओं से युक्त ये स्मार्टफोन युवाओं को डिजिटल शिक्षा, ऑनलाइन प्रशिक्षण, कौशल विकास कार्यक्रमों एवं शासकीय योजनाओं की जानकारी से सीधे जोड़ने में सहायक होंगे। साथ ही 31 युवाओं को मेसन किट उपलब्ध कराकर उन्हें निर्माण कार्यों में रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ने का मार्ग प्रशस्त किया गया है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें।

70 आत्मसमर्पित युवाओं को स्मार्टफोन, 31 को रोजगारोन्मुख मेसन किट प्रदान

पुनर्वास केवल आत्मसमर्पण तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भरता, सम्मानजनक जीवन और स्थायी आजीविका से जुड़ा समग्र प्रयास है। इसी सोच के अनुरूप 70 युवाओं को सैमसंग गैलेक्सी 5जी स्मार्टफोन प्रदान किए गए। 50 मेगापिक्सल डुअल कैमरा एवं 5000 मेगाहर्ज फास्ट चार्जिंग बैटरी जैसी आधुनिक सुविधाओं से युक्त ये स्मार्टफोन युवाओं को डिजिटल शिक्षा, ऑनलाइन प्रशिक्षण, कौशल विकास कार्यक्रमों एवं शासकीय योजनाओं की जानकारी से सीधे जोड़ने में सहायक होंगे।

कलेक्टर ने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य केवल आत्मसमर्पण सुनिश्चित करना नहीं, बल्कि इन युवाओं को सम्मानजनक एवं सुरक्षित जीवन उपलब्ध कराना है। पुनर्वास केंद्र के माध्यम से उन्हें कौशल प्रशिक्षण, शिक्षा एवं रोजगार के अवसरों से जोड़ा जा रहा है, ताकि वे समाज की मुख्यधारा में सशक्त रूप से आगे बढ़ सकें।

प्रतापगिरी, तोंगपाल निवासी श्री भीमा ने बताया कि लगभग 15 वर्षों तक नक्सल संगठन से जुड़े रहने के बाद पुनर्वास का निर्णय उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय सिद्ध हुआ है। पुनर्वास केंद्र में उन्हें आवास, भोजन एवं प्रशिक्षण की समुचित सुविधा मिल रही है तथा वे राजमिस्त्री का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। स्मार्टफोन मिलने से वे डिजिटल माध्यम से नई जानकारियां प्राप्त कर सकेंगे।

सिंघनपारा, बड़े सेटी निवासी श्री बुधरा ने भी पुनर्वास केंद्र की व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि यहां का जीवन सुरक्षित एवं सम्मानजनक है। प्रशासन द्वारा उन्हें मोबाइल, मेसन किट के साथ-साथ आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड एवं जॉब कार्ड भी प्रदान किया गया है। किसी भी तरह कि समस्या आने पर जिला प्रशासन द्वारा त्वरित समाधान किया जाता है। छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति केवल एक प्रशासनिक पहल नहीं, बल्कि विश्वास, विकास एवं सामाजिक समरसता की सशक्त मिसाल बनी है।

रायपुर में गूंजा राष्ट्रभक्ति और नारी शक्ति का संदेश

'मैं भारत हूं' थीम पर भव्य बाइक-स्कूटी रैली, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर में 'मैं भारत हूं' थीम पर भव्य बाइक-स्कूटी रैली का आयोजन किया गया। मातृशक्ति की ऐतिहासिक भागीदारी से सजी इस रैली में 2000 से अधिक महिलाओं ने हिस्सा लिया और राष्ट्रभक्ति, अनुशासन तथा महिला सशक्तिकरण का सशक्त संदेश दिया। यह रैली अपनी विशिष्टता और व्यापक सहभागिता के कारण गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज की गई।

रैली का शुभारंभ माँ काली मंदिर से हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत सामूहिक वंदे मातरम् गान के साथ हुई। इसके बाद अखिल भारतीय धर्मजागरण समन्वय कार्यसमिति सदस्य श्री राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव और श्रीमती विभा अवस्थी ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली का नेतृत्व महिला पुलिस कर्मियों के अनुशासित दस्ते ने किया, जिसके पीछे हजारों महिलाएं हाथों में तिरंगा लिए उत्साहपूर्वक आगे बढ़ीं।

यह रैली माँ काली मंदिर से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए श्रीराम मंदिर, वीआईपी चौक पर संपन्न हुई। रास्ते भर नागरिकों ने पुष्पवर्षा कर रैली का स्वागत किया। कार्यक्रम की संयोजिका डॉ. भारवि वैष्णव और सह-संयोजिका तथा नगर निगम पार्षद डॉ. अनामिका सिंह के नेतृत्व में पूरे आयोजन का सफल संचालन किया गया।

समापन समारोह में उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा भी शामिल हुए। उन्होंने महिलाओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि समाज में यातायात नियमों का पालन करने का संदेश देने के लिए आज महिलाओं ने जो स्कूटी रैली निकाली वह गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गयी है यह हमारे लिए गर्व का विषय है। उन्होंने अपने जीवन में अपनी बुआ अपनी मां अपनी पत्नी जैसी सशक्त महिलाओं के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि महिलाएं पुरुषों से अधिक सहनशील और ज्यादा मजबूत होती हैं।

उन्होंने स्वामी विवेकानंद के प्रेरक प्रसंग को याद करते हुए कहा कि यदि आज भारत की संस्कृति शाश्वत है, इस अविरल संस्कृति और सभ्यता को कोई आगे लेकर जाने वाला है तो वह भारत की महिलाएं हैं। अगर जीजा बाई ना होती तो शिवाजी का अस्तित्व नहीं होता और कौशल्या माता के संस्कार से ही तो भगवान श्री राम का अस्तित्व है। हर कामियाब व्यक्ति के पीछे महिला का हाथ होता है।

उन्होंने कहा कि आज महिलाएं शासन की योजनाओं का लाभ लेकर लखपति दीदी से करोड़पति दीदी तक का सफर तय कर रहीं हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का भी कार्य कर रही हैं। महिलाओं के संकल्प के आगे कोई टिक नहीं सकता आज नक्सलावाद के नासूर को जड़ से मिटाने के लिए दिन रात पहाड़ों में रहकर कार्य करने वाली पुलिस विभाग की महिलाओं का भी उन्होंने अभिनंदन किया।

गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अधिकृत उद्घोषक सोनल शर्मा ने घोषणा करते हुए कहा कि समाज में सकारात्मक संदेश देने और यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित यह स्कूटी रैली गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल की गई है, जो रायपुर और पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय है।

अखिल भारतीय धर्मजागरण विभाग के प्रमुख श्री राजेंद्र सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि संगठित मातृशक्ति ही राष्ट्र की वास्तविक शक्ति और संस्कृति की संरक्षक है। वहीं बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ वर्णिका शर्मा ने कहा कि आज की नारी हर क्षेत्र में अग्रणी है और यह आयोजन महिलाओं के आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता का प्रतीक है।

आयोजन की संयोजिका डॉ. भारवि वैष्णव ने कहा कि रायपुर की सड़कों पर उमड़ा मातृशक्ति का यह जनसैलाब भारतीय नारी के राष्ट्रप्रेम और समर्पण का प्रमाण है। वहीं डॉ. अनामिका सिंह ने कहा कि महिला सशक्तिकरण तभी पूर्ण है जब नारी मानसिक और सामाजिक रूप से सशक्त हो। उन्होंने कार्यक्रम के सफल आयोजन में सहयोग देने के लिए पुलिस प्रशासन और स्वयंसेवकों का आभार व्यक्त किया।

इस अवसर पर विभिन्न महिला संगठनों ने इस आयोजन में सहभागिता की और सभी प्रतिभागियों को हेलमेट भी प्रदान किया गया। सभी ने राष्ट्र की एकता, अखंडता और आदर्श नागरिक कर्तव्यों के पालन का संकल्प लिया। हाथों में तिरंगा और 'भारत माता की जय' के उद्घोष के साथ संपन्न हुई यह रैली महिला शक्ति, संस्कार और आत्मविश्वास का प्रेरक उदाहरण बन गई।

वित्त मंत्री चौधरी के SANKALP का बजट, अबूझमाड़ और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों पर जोर

छत्तीसगढ़ सरकार का 1.72 लाख करोड़ का बजट पेश

वित्त मंत्री ओपी चौधरी छत्तीसगढ़ राज्य का बजट पेश किया.आपको बता दें कि विष्णुदेव साय की सरकार का यह तीसरा बजट है. वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 1.72 लाख करोड़ का बजट पेश किया है. वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट की थीम संकल्प रखा है.

संकल्प का मतलब (SANKALP)

S- समावेशी
A-अधोसंरचना
N-निवेश
K-कुशल मानव संसाधन
A-अंत्योदय
L-लाइवलीहुड
P- पालिसी से परिणाम तक

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट भाषण की शुरुआत करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम विष्णुदेव साय को ज्ञापित किया. उन्होंने बजट की शुरुआत में GATI का जिक्र किया.

GATI का अर्थ है-

G- Good Governance
A - Accelerating Infrastructure
T- Technology
I- Industrial Growth

वित्त मंत्री ने इस दौरान कहा कि GATE न केवल ज्ञान के कल्याण के लिये अनिवार्य है, बल्कि हमारे 2030 तक के मध्यकालिक लक्ष्य और 2047 तक के 'विकसित छत्तीसगढ़' के दीर्घकालिक लक्ष्य को भी प्राप्त करने के लिये जरूरी है.

छत्तीसगढ़ के लिए 5 मिशन के लिए बजट का प्रावधान

- मुख्यमंत्री AI मिशन
- मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन
- मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन
- मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन
- मुख्यमंत्री स्टार्टअप और निपुण मिशन

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम अरुण साव ने बजट की प्रशंसा की है और इसे छत्तीसगढ़ के विकास को गति देने वाला बताया है.

बस्तर के विकास पर बजट पर फोकस

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि बस्तर-सरगुजा के लिए बस सेवा के लिए इस बजट में 10 करोड़ का प्रावधान किया गया. जिसमें बस्तर विकास प्राधिकरण के लिए 75 करोड़, दो एजुकेशनल सिटी की स्थापना के लिए 100 करोड़,अबूझमाड़ और जगरगुंडा में शुरु होगी एजुकेशन सिटी. सरगुजा मैनपाट के विकास के लिए 5 करोड़, नोनी के 18 वर्ष पूरी होने पर 1.50 लाख देंगे.बस्तर और सरगुजा के मेडिकल कॉलेज के लिए 50 -50 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है.

आंगनबाड़ी और महतारी वंदन योजना के लिए प्रावधान

आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए 52 करोड़ का प्रावधान, 500 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण होगा. महतारी सदन के लिए 75 करोड़ का प्रावधान.महतारी वंदन योजना के लिए 8200

करोड़ का प्रावधान. लखपति दीदी के लिए मुख्यमंत्री लखपति भ्रमण योजना की शुरुआत होगी. इंद्रावती बैराज बनाने के लिए 68 करोड़ रुपए का प्रावधान. आयुष्मान योजना के लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान,एनएचएम के लिए 2 हजार करोड़ का प्रावधान, बस्तर विकास के लिए 100 करोड़ का प्रावधान करने का ऐलान वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने किया है.मुख्यमंत्री द्रुतगामी सड़क योजना का भी ऐलान बजट में किया गया है.

बजट की बड़ी बातें

- ग्राम विकास योजना के लिए 1700 करोड़ का प्रावधान
- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 475 करोड़ का प्रावधान
- मुख्यमंत्री ग्राम गौरव योजना के लिए 100 करोड़ योजना
- पीएम ग्रामीण आवास 4 हजार करोड़ का प्रावधान
- वीबी जी राम जी योजना के क्रियान्वयन के लिए 4 हजार करोड़
- पीएम श्री योजना के तहत 350 स्कूलों को मॉडल स्कूल में विकसित
- स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट शाला योजना का शुभारंभ होगा
- प्रथम चरण में 150 विद्यालय चयनित होंगे,इसके लिए 100 करोड़ का प्रावधान
- 1587 पदों के लिए भर्ती हुई, 1500 नई पदों का सृजन
- 4000 से अधिक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया
- 15 साइबर थानों की स्थापना हुई, 5 नए साइबर थाने होंगे स्थापित
- 15 नए पुलिस थानों की होगी स्थापना
- महिला थानों की संख्या बढ़ेंगी
- 25 पुलिस थानों के नए भवन बनेंगे
- पुलिस में सीन ऑफ क्राइम विभाग के लिए 5 करोड़ का प्रावधान
- वन विभाग में 1 हजार से अधिक पदों का सृजन
- तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए 50 करोड़ का प्रावधान
- अभयारण्यों के लिए 11 करोड़ का प्रावधान
- स्कूल भवन निर्माण के लिए 123 करोड़ का प्रावधान
- NCC कैडेट्स के स्वल्पाहार की राशि भी दोगुना
- 25 विकास केंद्रों में खुलेंगे डायलिसिस केंद्र
- रायपुर में पहला होम्योपैथिक कॉलेज
- खाद्य पदार्थ और औषधि की जांच के लिए लैब
- सड़कों को टू लेन में उन्नयन किया जाएगा
- इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 9400 करोड़
- मेकाहारा हॉस्पिटल को AI के जरिए अपग्रेड किया जाएगा
- 150 करोड़ की लागत से नए गोदाम बनाए जाएंगे
- नवा रायपुर ऑप्टिकल फाइबर के लिए 10 करोड़
- मितानिन कल्याण निधि के लिए 350 करोड़
- बस्तर और सरगुजा में डॉक्टरों की भर्ती होगी
- PWD के लिए 9450 करोड़ रुपए का प्रावधान
- 206 गांवों को शहर से जोड़ने के लिए 250 करोड़
- स्टेट कैपिटल रीजन के लिए 68 करोड़ का प्रावधान
- रायपुर में खाद्य लैब का निर्माण होगा
- रानी दुर्गावति योजना के तहत बेटियों को राशि
- ट्रिपल आईटी के लिए 20 करोड़ का प्रावधान
- एयरपोर्ट विकास के लिए CG VAYU योजना
- CG VAYU योजना के लिए 30 करोड़ का प्रावधान
- रायपुर में अंडरग्राउंड बिजली के लिए 100 करोड़ का प्रावधान
- जलसंसाधन के लिए 3500 करोड़ रुपए का बजट
- मिशन अमृत योजना के लिए 512 करोड़ का प्रावधान
- 8 लाख करोड़ से अधिक के निवेश के प्रस्ताव राज्य को प्राप्त
- 23 औद्योगिक क्षेत्रों के लिए 250 करोड़
- भिलाई में इलेक्ट्रॉनिक कलस्टर 10 करोड़
- छग चैंबर ऑफ कॉमर्स के भवन के लिए प्रावधान
- निवेश को बढ़ावा देने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू
- कॉलेज को सेंटर ऑफ एक्सिलेंस बनाने पर जोर
- 731 करोड़ रुपए विश्वविद्यालयों के लिए
- 5 शासकीय महाविद्यालय का उन्नयन 15 करोड़
- 25 कॉलेज भवनों के उन्नयन हेतु 25 करोड़
- परीक्षा केंद्र भवन के लिए 25 करोड़ का प्रावधान
- स्वामी विवेकानंद भिलाई इंस्टीट्यूट के लिए 20 करोड़
- मेडिकल कॉलेज इंटर्न भवन के लिए 35 करोड़
- एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट के लिए 10 करोड़
- मुख्यमंत्री शिक्षा सहयोग योजना के लिए 10 करोड़
- व्यापमं की क्षमता विस्तार पर जोर दिया जाएगा
- मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के लिए 5 हजार करोड़ का प्रावाधान
- राशन के लिए 1 हजार करोड़ का प्रावधान
- बुजुर्ग दिव्यांग और असहाय लोगों के पेंशन के लिए 1422 करोड़
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए 5 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान
- दृष्टि बाधित विद्यालयों के लिए 7 करोड़ का प्रावधान
- नशा मुक्ति केंद्र संचालन के लिए 20 करोड़ का प्रावधान
- सत्यसाईं संजीवनी हॉस्पिटल के लिए 25 करोड़ का प्रावधान
- बीजापुर में प्रयास आवास विद्यालय के लिए प्रावधान
- रायपुर दुर्ग बिलासपुर में CGIT खोलने का ऐलान
- बैगा एवं पुजारी के लिए 3 करोड़ से अधिक का प्रावधान
- विभागाध्यक्ष कार्यालय का सेटअप होगा तैयार
- बाबा गुरुघासीदास जयंती के लिए राशि का प्रावधान
- 4 अनुसूचित जाति जनजाति विद्यालयों के लिए 50 करोड़
- गिरौदपुरी के लिए 5 करोड़ 60 लाख का प्रावधान
- ओबीसी के लिए विभागाध्यक्ष पदों के लिए प्रावधान
- ओबीसी बेटियों के पोस्टमैट्रिक छात्रावास का प्रावधान
- बिलासपुर में ओबीसी के लिए प्रयास आवासीय विद्यालय 20 करोड़ का प्रावधान
- किसानों और मजदूरों का दुर्घटना बीमा का प्रावधान
- कृषक उन्नति योजना के लिए 10 हजार करोड़ का प्रावधान
- मार्कफेड के लिए 6 हजार करोड़ का प्रावधान
- कृषि पंपों के लिए 5500 करोड़ का प्रावधान
- उद्यानिकी में पाम ऑयल उत्पादकों के लिए 150 करोड़ का प्रावधान
- आलू प्रसंस्करण योजना के लिए प्रावधान
- फसल बीमा के लिए 820 करोड़ का प्रावधान
- कृषक विकास के लिए 150 करोड़ का प्रावधान
- सिंचाई 130 करोड़ का प्रावधान
- मत्स्य खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 करोड़ का प्रावधान
- डेयरी समग्र विकास योजना के लिए 90 करोड़ का प्रावधान
- रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर में मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट का विस्तार
- हस्तशिल्पियों के लिए वित्तीय सहयोग मिलेगा
- रायपुर में यूनिटी मॉल का निर्माण 93 करोड़ का प्रावधान

आदिवासी अस्मिता या चुनावी राजनीति? बंगाल में नया विवाद

महिला दिवस की पूर्व संध्या पर भारतीय राजनीति में एक ऐसा विवाद सामने आया, जिसने केवल राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप को ही नहीं बढ़ाया, बल्कि देश की संवैधानिक मर्यादाओं, आदिवासी अस्मिता और महिला सम्मान को भी बहस के केंद्र में ला खड़ा किया। विवाद की शुरुआत पश्चिम बंगाल में आयोजित एक आदिवासी सम्मेलन से हुई, जहां देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी और राज्य सरकार की भूमिका को लेकर गंभीर आरोप लगे।

भाजपा की ओर से इस मुद्दे को जोरदार ढंग से उठाया गया। पार्टी की महिला इकाई की राष्ट्रीय अध्यक्ष वनाथी श्रीनिवासन ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य सरकार के किसी भी वरिष्ठ मंत्री ने राष्ट्रपति का स्वागत नहीं किया। उनके अनुसार, संथाल आदिवासी सम्मेलन जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम में राष्ट्रपति की मौजूदगी के बावजूद राज्य सरकार की यह दूरी केवल प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि एक गंभीर राजनीतिक संदेश है।

भाजपा का आरोप यहीं तक सीमित नहीं रहा। पार्टी नेताओं ने कहा कि कार्यक्रम की जगह अंतिम समय में बदलकर एक अपेक्षाकृत छोटे स्थान पर कर दी गई, जिससे अव्यवस्था की स्थिति बनी। यह भी कहा गया कि राष्ट्रपति ने स्वयं इस बदलाव को लेकर नाराजगी जताई थी। भाजपा ने इस घटना को केवल एक प्रशासनिक घटना नहीं, बल्कि 'संवैधानिक पद का अपमान' बताया।

इस विवाद को राष्ट्रीय स्तर पर तब और तूल मिला जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी इस मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि महिला दिवस के अवसर पर देश महिलाओं के सम्मान की बात कर रहा है, लेकिन इसी समय पश्चिम बंगाल में देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति का अपमान हुआ है। प्रधानमंत्री ने इसे केवल राजनीतिक विवाद नहीं, बल्कि एक सामाजिक और सांस्कृतिक असंवेदनशीलता का उदाहरण बताया। उनका कहना था कि राष्ट्रपति एक आदिवासी परंपरा के उत्सव में शामिल होने गई थीं, लेकिन राज्य सरकार ने कार्यक्रम से दूरी बनाकर गलत संदेश दिया। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि बंगाल की जनता इस व्यवहार को स्वीकार नहीं करेगी।

इस पूरे विवाद के बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बयान भी चर्चा में रहा। उन्होंने सार्वजनिक रूप से पश्चिम बंगाल को अपनी 'मायका' बताते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को छोटी बहन कहा और यह सवाल भी उठाया कि आखिर मुख्यमंत्री कार्यक्रम में क्यों नहीं आईं। उन्होंने कार्यक्रम स्थल बदलने को लेकर भी असंतोष व्यक्त किया।

लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए पलटवार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा चुनाव से पहले राजनीतिक लाभ के लिए राष्ट्रपति के पद

असल में यह विवाद कई स्तरों पर महत्वपूर्ण है। पहला सवाल संवैधानिक मर्यादा का है। राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद है और उनके साथ जुड़े कार्यक्रमों में प्रोटोकॉल का पालन केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के सम्मान का प्रतीक माना जाता है। दूसरा पहलू आदिवासी राजनीति का है।

का इस्तेमाल कर रही है। कोलकाता में एक धरना स्थल पर बोलते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा इतनी नीचे गिर चुकी है कि वह राष्ट्रपति कार्यालय को भी राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि राष्ट्रपति के कार्यक्रम में राज्य सरकार के प्रतिनिधि मौजूद थे और जो जानकारी राष्ट्रपति तक पहुंचाई गई, वह पूरी तरह सही नहीं थी।

ममता बनर्जी ने यह तर्क भी दिया कि चुनावी समय में हर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की मौजूदगी संभव नहीं होती। उन्होंने भाजपा पर यह आरोप लगाया कि वह पश्चिम बंगाल में आदिवासी विकास के मुद्दे को राजनीतिक रंग देकर राज्य सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। यहीं से यह विवाद एक साधारण प्रोटोकॉल विवाद से आगे बढ़कर व्यापक राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन गया। एक तरफ भाजपा इसे आदिवासी सम्मान और संवैधानिक गरिमा का मुद्दा बता रही है, तो दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस इसे चुनावी राजनीति का हिस्सा मान रही है।

असल में यह विवाद कई स्तरों पर महत्वपूर्ण है। पहला सवाल संवैधानिक मर्यादा का है। राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद है और उनके साथ जुड़े कार्यक्रमों में प्रोटोकॉल का पालन केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के सम्मान का प्रतीक माना जाता है। दूसरा पहलू आदिवासी राजनीति का है। द्रौपदी मुर्मू केवल भारत की राष्ट्रपति ही नहीं, बल्कि देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी हैं। इसलिए उनके सम्मान या अपमान की चर्चा स्वाभाविक रूप से आदिवासी अस्मिता के प्रश्न से भी जुड़ जाती है।

तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण पहलू चुनावी राजनीति का है। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनावों की पृष्ठभूमि में हर राजनीतिक घटना को नए अर्थ मिल जाते हैं। भाजपा लंबे समय से बंगाल में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है, जबकि तृणमूल कांग्रेस अपने गढ़ को बचाने में लगी है। ऐसे में राष्ट्रपति से जुड़ा यह विवाद केवल एक प्रोटोकॉल बहस नहीं रह जाता, बल्कि वह चुनावी विमर्श का हिस्सा बन जाता है। भाजपा इसे आदिवासी सम्मान और महिला गरिमा का मुद्दा बना रही है, जबकि तृणमूल कांग्रेस इसे राजनीतिक साजिश के रूप में पेश कर रही है।

महिला दिवस की पूर्व संध्या पर सामने आया यह विवाद हमें यह भी याद दिलाता है कि भारतीय राजनीति में प्रतीकों का कितना महत्व है। राष्ट्रपति, आदिवासी पहचान और महिला नेतृत्व – ये तीनों प्रतीक इस विवाद में एक साथ मौजूद हैं। यदि इस पूरे घटनाक्रम को देखें, तो यह केवल दो नेताओं के बीच की राजनीतिक बहस नहीं है। यह उस भारत की कहानी भी है, जहां सम्मान और राजनीति अक्सर एक ही मंच पर खड़े दिखाई देते हैं। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में यह विवाद केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रहता है या फिर यह पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनकर उभरता है। लेकिन इतना तय है कि महिला दिवस के पहले उठा यह सवाल केवल राजनीति का नहीं, बल्कि संवैधानिक गरिमा और सामाजिक संवेदनशीलता का भी है।

नीतीश कुमार की नई सधी हुई बिहारी चाल

"नीतीश कुमार की राज्यसभा सदस्यता की पुरानी 'अधूरी हसरत' अब पूरी हो रही है, क्योंकि वे विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा तो रह चुके हैं, लेकिन राज्यसभा नहीं। वहीं, राज्यसभा सदस्य बनने के बाद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री, उपप्रधामंत्री, उपसभापति, कद्दावर केंद्रीय मंत्री बनने की उनकी नई सम्भावनाएं बनेंगी।

राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि भाजपा की सलाह पर यह निर्णय लिया गया लगता है, क्योंकि 2025 विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत के बाद बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी (89 सीटें) बन गई है। इससे बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री बनना आसान हो सकता है, जबकि नीतीश के बेटे निशांत को डिप्टी सीएम बनाए जाने की चर्चा है।

बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड सुप्रीमो नीतीश कुमार राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी हैं। सियासत के चाणक्य श्री कुमार ने भाजपा के दबाव में नहीं, बल्कि अपनी केंद्रीय राजनीतिक संभावनाओं को उभारने के लिए दिल्ली कूच करने का अप्रत्याशित फैसला लिया है। भले ही उन्होंने राज्यसभा जाने का निर्णय बिहार की राजनीति में अपेक्षित एक बड़े बदलाव के हिस्से के रूप में लिया है, लेकिन यह भी उनकी लंबे समय से चली आ रही एक अधूरी इच्छा को प्रकट/पूरा करता है।

राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक, भाजपा के ओबीसीकरण के दृष्टिगत राष्ट्रीय स्तर पर सवर्णों की भाजपा नीत एनडीए से बेरुखी से उपजी सियासी परिस्थितियों का लाभ उठाने के लिए ही उन्होंने यह नया कदम उठाया है, जिसे एक तीर से कई निशाने के तौर पर देखा जाने लगा है। देश की समाजवादी राजनीति में भी अब उनका कोई निकट प्रतिद्वंद्वी नहीं बचा है। इसलिए गुरुवार, 5 मार्च 2026 को राज्यसभा की सदस्यता हेतु नामांकन दाखिल करने के साथ ही उनका अब नया भविष्य भी जुड़ा है।

समझा जाता है कि नीतीश कुमार की राज्यसभा सदस्यता की पुरानी 'अधूरी हसरत' अब पूरी हो रही है, क्योंकि वे विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा तो रह चुके हैं, लेकिन राज्यसभा नहीं। वहीं, राज्यसभा सदस्य बनने के बाद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री, उपप्रधामंत्री, उपसभापति, कद्दावर केंद्रीय मंत्री बनने की उनकी नई सम्भावनाएं बनेंगी। वहीं राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका बढ़ाने के लिए भी उनका यह कदम देखा जा रहा है, जहां वे बिहार, सामाजिक न्याय और विकास मुद्दों पर प्रभाव डाल सकें।

राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि भाजपा की सलाह पर यह निर्णय लिया गया लगता है, क्योंकि 2025 विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत के बाद बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी (89 सीटें) बन गई है। इससे बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री बनना आसान हो सकता है, जबकि नीतीश के बेटे निशांत को डिप्टी सीएम बनाए जाने की चर्चा है। हालांकि, जदयू में उनके इस फैसले पर असंतोष है, लेकिन इसे उनका व्यक्तिगत निर्णय बताया जा रहा है।

वहीं विपक्ष इसे बीजेपी का 'मास्क' हटाने का प्रयास मान रहा है। इससे राजद को पुन: सियासी ऑक्सीजन मिल सकता है। यूँ तो नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद बिहार के नए मुख्यमंत्री की घोषणा अभी स्पष्ट रूप से नहीं हुई है, क्योंकि यह प्रक्रिया राज्यसभा चुनाव के परिणाम (16 मार्च 2026) के बाद शुरू होगी। एनडीए में बीजेपी का सबसे बड़ा दावा माना जा रहा है, क्योंकि उनके पास 89 विधायक हैं।

हालांकि, संभावित उम्मीदवार के तौर पर सम्राट चौधरी, वर्तमान डिप्टी सीएम और भाजपा विधायक दल नेता, जिनकी दावेदारी सबसे मजबूत है। उनके पास गृह मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभाग हैं और राजनीतिक अनुभव समृद्ध है। वहीं, विजय कुमार सिन्हा- उपमुख्यमंत्री व पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, आक्रामक शैली के लिए जाने जाते हैं, लेकिन सम्राट से थोड़ा पीछे हैं। वहीं नित्यानंद राय- केंद्रीय मंत्री, BJP से प्रमुख नाम हैं, लेकिन नया चेहरा भी संभव है। अन्य चर्चाएंओं में नीतीश के बेटे निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाए जाने की संभावना है, क्योंकि उनका कोई स्वतंत्र चुनावी आधार नहीं है।

जदयू नेता विजय चौधरी ने पुष्टि की कि भाजपा से ही मुख्यमंत्री बनेगा। यह बदलाव एनडीए की आंतरिक रणनीति का हिस्सा लगता है। इससे भी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रभावित होगा। वहीं, निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाने का विचार मुख्य रूप से नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत को सुरक्षित रखने के लिए उठाया जा रहा है। वे लो-प्रोफाइल जीवन जीते रहे हैं, लेकिन पिता के राज्यसभा जाने के बाद जदयू में उनकी एंट्री तय मानी जा रही है।

जहां तक राजनीतिक रणनीति की बात है तो नीतीश के राष्ट्रीय स्तर पर जाने से बिहार में भाजपा को मुख्यमंत्री पद मिलेगा, जबकि निशांत को डिप्टी सीएम बनाकर जदयू का प्रभाव कायम रहेगा। हालांकि एनडीए की बैठक में इस पर मुहर लगने की चर्चा है, जो सत्ता समीकरण को संतुलित करेगी। वहीं निशांत अब तक सियासत से दूर रहे, लेकिन उनकी नियुक्ति पिता की लंबी राजनीतिक यात्रा को आगे बढ़ाने का प्रयास है। यह कदम जदयू कार्यकर्ताओं को एक नया चेहरा देकर पार्टी को मजबूत करने के उद्देश्य से है। इसके अलावा मोदी के हनुमान लोजपा कोटे से केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की सियासत को चमकाने के लिए भी यह नया फेरबदल संभावित प्रतीत होता है।

- माटी शिल्प कला को बाजार देने 2 करोड़ 86 लाख
- राजस्व रिफॉर्म करने के लिए 25 करोड़ का प्रावधान
- साइबर तहसील के लिए बजट का प्रावधान
- ऑनलाइन सुविधा बढ़ाने के लिए 10 करोड़ का प्रावधान
- 15 स्थानों में उपपंजीयक भवन के लिए प्रावधान
- मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पोर्टल के लिए 22 करोड़
- छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 के लिए यूनिट 3 करोड़ का प्रावधान
- 50 लाख तक के निर्माण कार्यों की एजेंसी ग्राम पंचायत
- शक्तिपीठ योजना के लिए 5 करोड़
- शक्तिपीठ सर्किट के विकास के लिए प्रावधान
- सिरपुर के विकास के लिए 36 करोड़
- श्रीरामलला दर्शन योजना के लिए 36 करोड़
- इको टूरिज्म के लिए प्रावधान
- 350 करोड़ की लागत से बन रही फिल्म सिटी
- कबीरधाम में भोरमदेव के विकास के लिए 146 करोड़
- प्रतिभाशाली छात्रों को छत्तीसगढ़ दर्शन के लिए 5 करोड़
- कोपरा जलाशय रामसर साइट के लिए प्रावधान
- धार्मिक स्थलों में रोपवे के लिए 35 करोड़ का प्रावधान
- विवेकानंद की स्मृति देव भवन के उत्थान के लिए 5 करोड़
- रायपुर साहित्य उत्सव के लिए बजट में प्रावधान
- छत्तीसगढ़ अप्रवासी भारतीयों के लिए भी बजट
- जनसंपर्क का कुल बजट 475 करोड़
- ईवी वाहनों की सब्सिडी के लिए 6 करोड़
- ई ट्रैक निर्माण के लिए 15 करोड़ का प्रावधान
- खेलों के लिए 19 करोड़ का प्रावधान
- ओलंपिक पदक विजेताओं के लिए राशि का प्रावधान
- खेल अधोसंरचना विकास के लिए 45 करोड़
- शासकीय कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा
- कैशलेस उपचार के लिए 100 करोड़ का प्रावधान
- शासकीय कर्मचारियों के लिए भवन निर्माण के लिए 20 करोड़
- राजस्व रिफॉर्म करने के लिए 25 करोड़ का प्रावधान
- साइबर तहसील के लिए बजट का प्रावधान
- ऑनलाइन सुविधा बढ़ाने के लिए 10 करोड़ का प्रावधान
- 15 स्थानों में उपपंजीयक भवन के लिए प्रावधान
- मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पोर्टल के लिए 22 करोड़
- छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 के लिए यूनिट 3 करोड़ का प्रावधान
- 50 लाख तक के निर्माण कार्यों की एजेंसी ग्राम पंचायत
- ग्राम विकास योजना के लिए 1700 करोड़ का प्रावधान
- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 475 करोड़ का प्रावधान
- मुख्यमंत्री ग्राम गौरव योजना के लिए 100 करोड़ योजना
- पीएम ग्रामीण आवास 4 हजार करोड़ का प्रावधान
- वीबी जी राम जी योजना के क्रियान्वयन के लिए 4 हजार करोड़
- पीएम श्री योजना के तहत 350 स्कूलों को मॉडल स्कूल में विकसित
- स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट शाला योजना का शुभारंभ होगा
- प्रथम चरण में 150 विद्यालय चयनित होंगे,इसके लिए 100 करोड़ का प्रावधान
- स्कूल भवन निर्माण के लिए 123 करोड़ का प्रावधान
- NCC में स्वल्पाहार की राशि भी दोगुना
- वन विभाग में 1 हजार से अधिक पदों का सृजन
- तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए 50 करोड़ का प्रावधान
- अभयारण्यों के लिए 11 करोड़ का प्रावधान

शक्तिपीठ योजना के लिए 5 करोड़

- शक्तिपीठ सर्किट के विकास के लिए प्रावधान
- सिरपुर के विकास के लिए 36 करोड़
- श्रीरामलला दर्शन योजना के लिए 36 करोड़
- इको टूरिज्म के लिए प्रावधान
- 350 करोड़ की लागत से बन रही फिल्म सिटी
- कबीरधाम में भोरमदेव के विकास के लिए 146 करोड़
- प्रतिभाशाली छात्रों को छत्तीसगढ़ दर्शन के लिए 5 करोड़
- कोपरा जलाशय रामसर साइट के लिए प्रावधान
- धार्मिक स्थलों में रोपवे के लिए 35 करोड़ का प्रावधान
- विवेकानंद की स्मृति देव भवन के उत्थान के लिए 5 करोड़
- शासकीय कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा
- कैशलेस उपचार के लिए 100 करोड़ का प्रावधान
- शासकीय कर्मचारियों के लिए भवन निर्माण के लिए 20 करोड़
- ईज आफ इरंग बिजनेस को बढ़ावा देने की बात

इससे पहले वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि सरकारी सुविधाओं और योजनाओं की आसान और सुनिश्चित डिलीवरी के लिये हम डिजिटल गवर्नेंस का उपयोग कर रहे हैं.सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन पर सतत नजर रखने के लिये हमने अटल मॉनिटरिंग पोर्टल आरंभ किया है. इस बजट में इस हेतु 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है. सरकारी खरीद में भ्रष्टाचार रोकने के लिये हमने Gem Portal' से खरीदी को अनिवार्य कर दिया है. छत्तीसगढ़ में ईज आफ इरंग बिजनेस " EODB को बढ़ावा देने के लिये दृढ़ संकल्पित है. हमारे द्वारा प्रथम चरण में 20 विभागों के कुल 216 सुधारों को लागू करने का लक्ष्य रखा गया है.पूरी मुहिम बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान : BRAP का मूल उद्देश्य व्यवस्था में पारदर्शिता लाना तथा नियमों में सरलीकरण करके प्रक्रियाओं को आसान बनाना है.

आदर्श उप पंजीयक कार्यालय बनाने पर जोर

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि स्टाम्प और पंजीयन विभाग द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी का बेहतर उपयोग करते हुये आम जनता को सुविधा प्रदान करने के लिये अनेक कदम उठाये जा रहे हैं सुगम ऐप के माध्यम से फर्जी रजिस्ट्री को रोकने में मदद मिल रही है. अनेक प्रक्रियाओं को पेपरलेस और फेसलेस भी किया जा रहा है. पंजीयन के 20 मैदानी कार्यालयों को 'आदर्श उप पंजीयक कार्यालय' बनाने के लिये इस बजट में 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है. पासपोर्ट ऑफिस की तर्ज पर जमीन रजिस्ट्री हेतु भी लोगों के लिये आसान व्यवस्था स्थापित की जाएगी. हक त्याग एवं बेवारा में लगने वाले लाखों रुपये के शुल्क के स्थान पर मात्र 500 रुपये का प्रावधान कर दिया गया है, इससे भविष्य में उत्पन्न होने वाले लाखों राजस्व विवादों को रोका जा सकेगा.

उच्च स्तरीय जॉब के लिए प्रयास

सरकारी विभागों की कार्य कुशलता बढ़ाने, डाटा प्रबंधन को सशस्त बनाने और डिजिटल नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिये राज्य के उच्च तकनीकी शिक्षण संस्थानों के साथ मिलकर 'सीएम सुशासन फेलोशिप योजना' आरंभ की जा रही है. इसके लिये इस बजट में 10 करोड़ प्रावधान किया गया है. यह संभवत: पूरे देश में इस तरह का पहला प्रयास है कि IIM एवं IIIT के साथ मिलकर 'अन द जॉब ट्रेनिंग' शामिल करते हुये दस मानव संसाधन तैयार किए जाएंगे. इससे हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं को उच्च स्तरीय जॉब के अवसर प्राप्त हो सकेंगे.

'संकल्प से सिद्धि' का रोडमैप

बजट में समावेशी विकास, अधोसंरचना, निवेश, शिक्षा, कृषि और बस्तर-सरगुजा के समग्र उत्थान पर विशेष जोर

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट प्रदेश के सर्वांगीण विकास, अंत्योदय और आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ के निर्माण के संकल्प को साकार करने वाला बजट है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का पहला बजट 'ज्ञान' और दूसरा बजट 'गति' की थीम पर आधारित था, जबकि इस वर्ष का बजट 'संकल्प' की भावना को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है, जो विकसित भारत-विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में निर्णायक कदम सिद्ध होगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इस बजट में समावेशी विकास, अधोसंरचना सुदृढ़ीकरण, निवेश संवर्धन, कुशल मानव संसाधन निर्माण, लाइवलीहुड, अंत्योदय तथा 'पॉलिसी से परिणाम' तक की स्पष्ट रणनीति को प्राथमिकता दी गई है। यह बजट यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप प्रदेश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार मिशन मोड में कार्य करने के लिए पांच मुख्यमंत्री मिशन प्रारंभ कर रही है, जिनमें मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन, मुख्यमंत्री एआई मिशन, मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन, मुख्यमंत्री स्टार्टअप मिशन तथा मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन शामिल हैं। इन मिशनों के माध्यम से प्रदेश के विकास को नई दिशा, नई धार और नई गति मिलेगी।

उन्होंने कहा कि शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए स्कूल शिक्षा के लिए कुल बजट का 13.5 प्रतिशत प्रावधान किया गया है, जो सर्वाधिक है। बस्तर के अबूझमाड़ और जगरगुंडा में दो एजुकेशन सिटी स्थापित की जाएंगी, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों के लिए कैशलेस उपचार सुविधा हेतु भी बजट में प्रावधान किया गया है। औद्योगिक विकास को गति देने के लिए 23 नवीन औद्योगिक पार्कों की स्थापना हेतु 250 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वहीं शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना में 200 करोड़ रुपए तथा भूमि विकास बैंक के लिए भी 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और कृषि क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था की आधारशिला है। इसी को ध्यान में रखते हुए कृषि क्षेत्र के लिए 13 हजार 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी के अंतर की राशि का भुगतान एकमुश्त करने की व्यवस्था जारी रहेगी और इसके लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बस्तर और सरगुजा क्षेत्र का विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इन क्षेत्रों में खाद्य, कृषि और उससे जुड़े उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही बकरी पालन, सूअर पालन और मधुमक्खी पालन जैसे गतिविधियों को बढ़ावा देकर स्थानीय लोगों की आय बढ़ाने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि इंद्रावती नदी पर देवरगांव और मटनार बैराज निर्माण के लिए 2000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है, जिससे बस्तर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का विस्तार होगा और किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि माओवादी उन्मूलन में बस्तर फाइटर्स की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। उनके योगदान को ध्यान में रखते हुए बस्तर फाइटर्स में 1500 नई भर्तियों का प्रावधान किया गया है। पर्यटन और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए होमस्टे योजना हेतु 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और कनेक्टिविटी क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं, जिनमें कुनकुरी, मनेन्द्रगढ़, कबीरधाम, जांजगीर-चांपा एवं दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज संचालन, जगदलपुर-अंबिकापुर हवाई सेवाओं का विस्तार, अंदरूनी क्षेत्रों में मुख्यमंत्री बस सेवा तथा बस्तर एवं सरगुजा ओलंपिक्स के आयोजन शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि युवाओं के लिए भर्ती प्रक्रियाओं को तेज करने हेतु व्यापम की दक्षता बढ़ाने के प्रावधान किए गए हैं। साथ ही युवाओं के शैक्षणिक भ्रमण के लिए छत्तीसगढ़ युवा दर्शन योजना प्रारंभ की जाएगी तथा लखपति दीदियों के भ्रमण कार्यक्रम के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस बजट को प्रदेशवासियों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब बताते हुए वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी एवं उनकी पूरी टीम को बधाई दी और कहा कि यह बजट प्रदेश को समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक ले जाने में मील का पत्थर साबित होगा।

विधानसभा परिसर में मिलेट कैफे का शुभारंभ

छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने मिलेट कैफेटेरिया का उद्घाटन किया। डॉ. रमन सिंह ने मिलेट्स के व्यंजनों का स्वाद लिया और इसकी सराहना की। इस कैफे में मुख्यत: मिलेट्स से निर्मित व्यंजन एवं उत्पाद उपलब्ध है। यह देश में किसी भी विधानसभा परिसर में प्रारंभ होने वाला पहला मिलेट कैफे है। इस मिलेट कैफे का संचालन साथी परियोजना के अंतर्गत किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में साथी परियोजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य शासन द्वारा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालयए रायपुर को लीड नोडल एजेंसी तथा राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम को सहायक एजेंट नियुक्त किया गया है। इस् अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के अध्यक्ष श्री चंद्रहास चंद्राकर, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल, विधानसभा सचिव श्री दिनेश शर्मा, नोडल अधिकारी श्री गजेंद्र चंद्राकर, और अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे। बेमेतरा के विधायक ईश्वर साहू भी इस अवसर पर मौजूद थे। मिलेट कैफे का संचालन क्षीर सागर स्व-सहायता समूह के द्वारा किया जा रहा है।

विधानसभा परिसर में मिलेट कैफे शुरू करने की पहल से छत्तीसगढ़ राज्य के जन प्रतिनिधियों में मिलेट के प्रति जागरूकता को बढ़ावा मिलेगा। महिला स्व-सहायता समूह के माध्यम से कैफे का संचालन किये जाने से महिला सशक्तिकरणए स्व-रोजगार सृजन तथा स्थानीय कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन को प्रोत्साहन मिलेगा।

खाड़ी देशों में नागरिकों से ज्यादा विदेशी, बसे हैं 90 लाख भारतीय

ईरान में जारी युद्ध के बाद से खाड़ी देशों यानी गल्फ कंट्रीज की खूब चर्चा हो रही है. गौर करने वाली बात यह है कि प्रवासी भारतीयों की 25% आबादी से अधिक इन गल्फ कंट्रीज में रहती है. सबसे अधिक प्रवासी भारतीय संयुक्त अरब अमीरात में रहते हैं और इनकी कुल आबादी लगभग 40 लाख के करीब बताई जाती है.

किसे कहा जाता है गल्फ कंट्री जो GCC के सदस्य हैं?

फारस की खाड़ी के आसपास स्थित छह देशों को गल्फ कंट्री या खाड़ी देश कहा जाता है. इनमें शामिल हैं-बहरीन,कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, सउदी अरब और कतर. ये छह देश जीसीसी (Gulf Cooperation Council) के सदस्य हैं. इस कौंसिल का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आर्थिक, सुरक्षा, राजनीतिक और सामाजिक सहयोग बढ़ाना है. जीसीसी की स्थापना 25 मई 1981 को हुई है, इसका मुख्यालय रियाद सऊदी अरब में है.

खाड़ी देशों में भारतीयों की आबादी

खाड़ी देशों में भारतीयों की एक बड़ी आबादी रोजगार के लिए जाती है. विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार खाड़ी देशों में लगभग 90 लाख भारतीय रहते हैं. इनके वहां जाने की वजह है रोजगार की उपलब्धता और बेहतर वेतन. 1970 के दशक में जब इन देशों में तेल की खोज हुई और निर्यात में तेजी आई तो इन देशों में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य की जरूरत पड़ी ताकि सड़क, बंदरगाह और अन्य जरूरी निर्माण कार्य कराए जा सकें, लेकिन इन देशों की आबादी बहुत कम थी,तब इन्होंने बाहर दे श्रमिक बुलाया और उसी दौरान भारत से बेहतर वेतन की चाह में मजदूर गए. बाद में स्वास्थ्य, होटल और आईटी सेक्टर में भी काम करने के लिए भारत से लोग खाड़ी देशों में गए. खाड़ी देशों में वेतन अन्य देशों की अपेक्षा ज्यादा मिलता है और यहां आय पर टैक्स नहीं देना पड़ता है, इस वजह से भारतीय खाड़ी देशों में नौकरी करना पसंद करते हैं.

> **"गल्फ देशों की खासियत यह है कि यहां की कुल आबादी में नागरिकों से ज्यादा संख्या विदेशियों की है, जो यहां रोजगार की तलाश में आते हैं. खाड़ी देशों में कतर एक ऐसा देश है, जहां नागरिकों की संख्या मात्र 12.1 प्रतिशत है और विदेशी यहां 87.9 प्रतिशत रहते हैं."**

खाड़ी देशों में लगभग 90 लाख भारतीय रहते हैं. इनकी संख्या सबसे अधिक संयुक्त अरब अमीरात में है. विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात में 3419875 प्रवासी भारतीय और कुल 3425144 भारतीय रहते हैं. सऊदी अरब में प्रवासी भारतीयों की संख्या 2592166 है, जबकि कुल भारतीयों की संख्या 2594947 है.

खाड़ी देशों की जनसंख्या का अनुपात

गल्फ देशों की खासियत यह है कि यहां की कुल आबादी में नागरिकों से ज्यादा संख्या विदेशियों की है, जो यहां रोजगार की तलाश में आते हैं. खाड़ी देशों में कतर एक ऐसा देश है, जहां नागरिकों की संख्या मात्र 12.1 प्रतिशत है और विदेशी यहां 87.9 प्रतिशत रहते हैं. दूसरे स्थान पर संयुक्त अरब अमीरात है जहां नागरिक 12.9 प्रतिशत और विदेशी 87.1 प्रतिशत रहते हैं.

और अमेरिका के रिश्ते बिगड़ते ही गये.

इस बीच ताकतवर अमेरिका से मुकाबले के लिए ईरान अपनी सैन्य क्षमता के विस्तार के साथ ही परमाणु ताकत विकसित करने की कोशिश में लगा रहा. दूसरी ओर, अमेरिका किसी भी तरीके से ईरान को परमाणु संपन्न होने से रोकने के लिए कमर कसे हुए है. इस जंग पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं आश्वस्त तो करती हैं, पर देखने की चीज यह है कि इनका कितना दबाव दोनों पक्षों पर पड़ता है और संयुक्त राष्ट्र इस पर क्या कदम उठाता है. फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने इस्राइल और ईरान, दोनों से हमले रोकने के लिए कहा है, तो रूस ने ईरान पर हमले रोकने की आलोचना की है, जबकि ब्रिटेन ने वार्ता से हल निकालने की बात कही है. जहां तक भारत की बात है, तो हमारे लिए ईरान और इस्राइल, दोनों महत्वपूर्ण हैं. इस्राइल के साथ हमने अपनी साझेदारी को हाल ही में और मजबूत किया, तो ईरान के साथ हमारे गहरे आर्थिक रिश्ते हैं. ईरान का अशांत रहना भारत की ऊर्जा जरूरतों के हित को बाधित कर सकता है. इस जंग से पश्चिम एशिया की शांति और स्थिरता दांव पर लगी है.

जबकि भारत के लिए पश्चिम एशिया का पूरा इलाका बेहद महत्वपूर्ण है, जहां लगभग एक करोड़ भारतीय रहते हैं. ईरान पर हमले से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने इस्राइल में कहा था कि मध्य एशिया की स्थिरता और शांति से भारत के हित जुड़े हैं. इस जंग पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने चिंता जतायी है और यह प्रतिक्रिया जतायी है कि हम सभी पक्षों से संयम बरतने, तनाव बढ़ने से बचने और आम लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने का आग्रह करते हैं. इसमें दोनों पक्षों को सुझाव देते हुए कहा गया है कि तनाव कम करने और अंदरूनी मुद्दों को सुलझाने के लिए बातचीत और डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाया जाना चाहिए. गौरतलब है कि शनिवार को ही भारत ने ईरान और इस्राइल में रहने वाले अपने नागरिकों को अत्यधिक सावधानी बरतने और सतर्क रहने की सलाह दी थी. ईरान स्थित भारतीय दूतावास ने भी अपने नागरिकों से सावधानी बरतने, आसपास की स्थितियों के प्रति जागरूक रहने और दूतावास से आगे मिलने वाले निर्देशों का इंतजार करने के लिए कहा है. जाहिर है, इस संकट से वैश्विक अनिश्चितता और बढ़ी ही है.

अमेरिकी ठिकानों के साथ-साथ संयुक्त अरब अमीरात के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर दुबई को भी निशाना बनाया है. उसने चेतावनी दी है कि इस्राइल-अमेरिकी हमलों का पूरी मजबूती से जवाब दिया जायेगा. उसने यह भी धमकी दी है कि हमला बेशक इस्राइल ने शुरू किया हो, लेकिन इसे खत्म ईरान करेगा. ईरान को हूती विद्रोहियों के अलावा हिजबुल्लाह का साथ मिल गया है. ईरान ने पहली बार सैकड़ों किलोमीटर दूर तक हमला कर अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया है. खाड़ी देशों में सुरक्षित माने जाने वाले संयुक्त अरब अमीरात में ईरानी मिसाइलों का गिरना बड़ी बात है.

अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी दशकों पुरानी है. वर्ष 1953 में ईरान के प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसद्दिक के तख्तापलट के साथ ईरान में अमेरिका-विरोध की बुनियाद पड़ी थी. दरअसल मोसद्दिक ने ईरान के हितों की रक्षा के लिए ब्रिटिश स्वामित्व वाली ऑयल कंपनी का राष्ट्रीयकरण कर दिया था. अमेरिका-ब्रिटेन ने उसे अपने रणनीतिक हितों के विरुद्ध माना और मोसद्दिक का तख्तापलट कर दिया. उसके बाद रजा पहलवी की सत्ता बहाल हुई. पहलवी के दौर में ईरान अमेरिका समर्थक और उसके हितों का संरक्षक बना रहा. लेकिन दो दशक बाद ईरान में पहलवी और अमेरिका का तीखा विरोध शुरू हुआ. फरवरी, 1979 में पहलवी ने जान बचाने के लिए ईरान छोड़ दिया. अयातुल्लाह खुमैनी की वापसी हुई और एक अप्रैल, 1979 से ईरान इस्लामी गणतंत्र घोषित हो गया. फिर तो ईरान

दिखने लगे हैं ईरान-अमेरिका युद्ध के साइड इफेक्ट्स

ईरान और अमेरिका/इजरायल के बीच चल रही लड़ाई का असर अब पूरी दुनिया पर दिखने लगा है। होर्मुज स्टेट से जहाजों की आवाजाही लगभग बंद हो गई है। दुनिया का 20 फीसदी तेल इसी रास्ते से गुजरता है। इस कारण तेल और गैस सप्लाई पर गंभीर संकट खड़ा हो गया है। कच्चे तेल की कीमत में शनिवार से अब तक करीब 20% तेजी आ चुकी है। इसी तरह गैस की कीमत में भी भारी उछाल देखी जा रही है। इराक में तेल के रोजाना उत्पादन में 15 लाख बैरल की कटौती कर दी है। कतर ने एलएनजी का उत्पादन बंद कर दिया है। सऊदी अरब की एक बड़ी रिफाइनरी ने भी प्रोडक्शन बंद है। ईरान ने इस रिफाइनरी पर हाल में दो बार हमला किया। जानकारों का कहना है कि अगर ईरान में लड़ाई जल्दी खत्म नहीं हुई तो कच्चे तेल की कीमत 150 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच जाएगी। इससे भारत, चीन और जापान जैसे देशों को भारी नुकसान हो सकता है जो अपना ज्यादातर तेल बाहर से खरीदते हैं। तेल महंगा होने से इन देशों की इकॉनमी बुरी तरह गड़बड़ा सकती है और महंगाई के बेकाबू होने का खतरा है।

भारत का हाल

दुनिया में एलएनजी के दूसरे बड़े उत्पादक देश कतर ने गैस का उत्पादन रोक दिया है। उसके एक प्लांट पर हाल में हमला हुआ था। भारत और चीन कतर की गैस के सबसे बड़ी खरीदार हैं। इससे भारत को होने वाली आपूर्ति प्रभावित हुई है और प्रमुख घरेलू क्षेत्रों के लिए ईंधन की उपलब्धता का संकट खड़ा हो गया है। भारत सालाना 2.7 करोड़ टन एलएनजी का आयात करता है, जिसमें से 40 प्रतिशत हिस्सा अकेले कतर से आता है।

होर्मुज स्ट्रेट बंद होने के कारण भारत की सबसे बड़ी एलएनजी आयातक पेट्रोनेट एलएनजी कतर में अपने जहाज नहीं भेज पा रही है। इसका मुख्य कारण हॉर्मुज स्ट्रेट का लगभग बंद होना है। भारत के लिए यह मार्ग अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि देश के कुल कच्चे तेल आयात का लगभग 50% और एलएनजी आपूर्ति का 54% इसी रास्ते से होकर आता है। भारत के पास 18 दिन का क्रूड, 21 दिन का पेट्रोल-डीजल और 12 दिन की गैस का स्टॉक है। अगर यह लड़ाई लंबी खिंची तो भारत की मुश्किल बढ़ सकती है।

आदिवासी नेतृत्व गढ़ रहा है विकास के नए सोपान

विष्णुदेव साय जनता के बीच के एक ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं जिनकी सदाशयता और दूरगामी योजनाओं से प्रदेश में विकास और प्रगति का राह आसान हुआ है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आदिवासी पृष्ठभूमि से आते हैं।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के जन्मदिवस पर विशेष

छगन लाल लोन्हारे
(उप संचालक जनसंपर्क)

छत्तीसगढ़ की खूबसूरत वादियों में स्थित जशपुर जिला के ग्राम बगिया में 21 फरवरी को जन्म लेने वाले मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय सज्जनता और सहृदयता की एक मिसाल है। दो वर्ष के अपने मुख्यमंत्रित्व काल में छत्तीसगढ़ राज्य में विकास का एक नया आयाम गढ़ने वाले तथा प्रदेश के नागरिकों के दिलों में राज करने वाले मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज अपनी लोकप्रियता के शिखर पर विद्यमान है। श्री विष्णुदेव साय जनता के बीच के एक ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं जिनकी सदाशयता और दूरगामी योजनाओं से प्रदेश में विकास और प्रगति का राह आसान हुआ है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आदिवासी पृष्ठभूमि से आते हैं।

केबिनेट बैठक में राज्य में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को 3100 रूपए प्रति क्विंटल के मान से अंतर की राशि होली पर्व से पहले एकमुश्त भुगतान किए जाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में 25 लाख 24 हजार 339 किसानों से 141.04 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कृषक उन्नति योजना के तहत धान के मूल्य के अंतर की राशि के रूप में लगभग 10 हजार करोड़ रूपए का भुगतान होली त्यौहार से पहले एकमुश्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री स्वयं एक किसान पुत्र हैं वे किसानों की पीड़ा को भलीभांति जानते हैं।

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कृषक उन्नति योजना के तहत राज्य के किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी 3100 रूपए प्रति क्विंटल के मान से की की गई है, जो देश में सर्वाधिक है। बीते दो वर्षों में कृषक उन्नति योजना के तहत राज्य के किसानों को धान के मूल्य के अंतर के रूप में 25 हजार करोड़ रूपए से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। इस साल होली से पूर्व किसानों को 10 हजार करोड़ रूपए का भुगतान होने से यह राशि बढ़कर 35 हजार करोड़ रूपए हो जाएगी। किसान हितैशी सरकार के इस निर्णय से बाजार भी गुलजार होंगे, जिससे शहरी अर्थव्यवस्था पर सीधा असर दिखाई देगा, ट्रैक्टर आदि की बिक्री में वृद्धि होगी।

प्रदेश की नवीन औद्योगिक नीति से राज्य में अब तक 7 लाख 83 हजार करोड़ रूपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने अपने दो साल के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ को पूरे देश में एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश की जनता के बीच जाकर जनता का न केवल विश्वास जीता है बल्कि उनके हित को ध्यान में रखकर उन्होंने ऐसी योजनाओं का क्रियान्वयन किया है जिससे छत्तीसगढ़ का समग्र विकास सम्भव हो पाया है। यह केवल और केवल श्री विष्णुदेव साय जैसे एक संवेदनशील, कर्मठ तथा ऊर्जावान

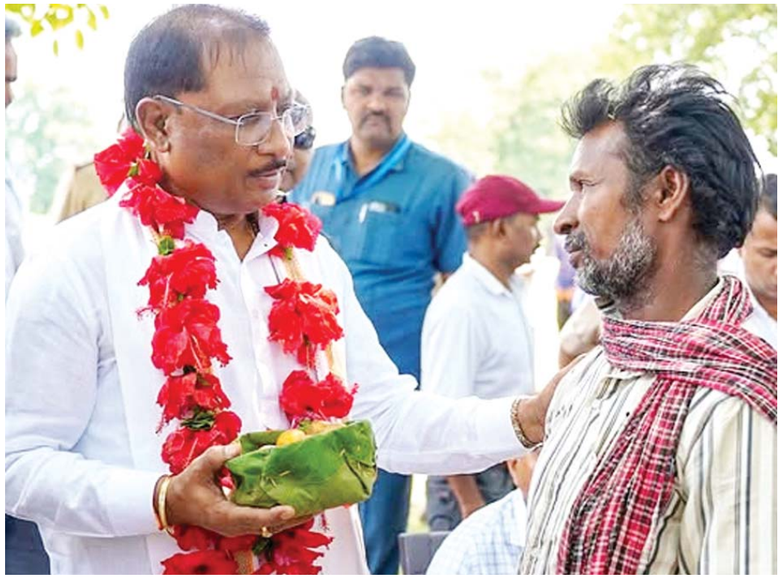

मुख्यमंत्री ही सम्भव कर सकते हैं।

श्री विष्णु देव की सुशासन में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्ष 2026 को महतारी गौरव वर्ष घोषित किया गया है। राज्य सरकार ने मातृशक्ति का सम्मान करते हुए 70 लाख महिलाओं को महतारी वंदन योजना के अंतर्गत प्रतिमाह 1000 रूपए की सहायता राशि प्रदान की जा रही है। प्रदेश के 42 हजार 878 महिला स्व-सहायता समूहों को आसान ऋण से अब तक 129.46 करोड़ रूपए का लाभ दिया गया है। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के अंतर्गत 4.81 लाख महिलाओं को 237 करोड़ रूपए की सहायता राशि दी गई है। राज्य की 19 लाख से अधिक महिलाओं को पूरक पोषण आहार सुनिश्चित की गई है। महिला सुरक्षा के लिए सखी वन स्टॉप सेंटर और महिला हेल्पलाइन 181 की स्थापना की गई है। महिलाओं को रोजगार मूलक कार्यों के जरिए स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंचायत स्तर पर 52.20 करोड़ की लागत से 179 महतारी सदनों का निर्माण कराया जा रहा है। महिला समूहों के उत्पादों की बिक्री हेतु 200 करोड़ की लागत से नवा रायपुर में यूनिटी मॉल का निर्माण कराया जाएगा। मुख्यमंत्री की पहल पर दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के अंतर्गत प्रदेश के 5.62 लाख भूमिहीन कृषि मजदूरों को प्रतिवर्ष 10 हजार रूपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है।

राज्य सरकार द्वारा आवास और सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रख कर अब तक 26 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास स्वीकृति किए गए हैं। स्वच्छ पेयजल सबका अधिकार है। प्रदेश के 41 लाख से अधिक घरों तक स्वच्छ पेयजल पहुंच रहा है। गुणवत्तापूर्ण जलापूर्ति के लिए राज्य में 77 जल परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई है। 70 समूह जल प्रदाय योजनाओं से प्रदेश के 3208 गांव लाभान्वित हो रहे हैं। इसके अलावा राज्य के शत-प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण किया जा रहा है।

डबल इंजन की सरकार में रावघाट-जगदलपुर रेल परियोजना के साथ रेल नेटवर्क मैप से बस्तर जुड़ रहा है। जगदलपुर-विशाखापट्नम और रायपुर-विशाखापट्नम नई सड़क परियोजनाओं से विकास की नई राहें खुल रही है। प्रदेश के 32 नगरीय निकायों में नॉलेज बेस्ड सोसाइटी हेतु लाइट हाउस निर्माण की पहल की जा रही है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलने का बीड़ा उठाया है। उन्होंने प्रदेश के हर वर्ग की बुनियादी सुविधाओं और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पीएम आवास योजना, कृषक उन्नति योजना, नियद नेल्ला नार, अखरा निर्माण योजना जैसी योजनाओं का शुभारम्भ किया है और जनता के बीच अपनी एक अलग छवि निर्मित की है।

मुख्यमंत्री श्री साय जनता के बीच और हर समुदाय के बीच एक ऐसा पुल बनाना जानते हैं जिससे सभी एक दूसरे से जुड़ सके और सभी प्रदेश के हित में अपनी-अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह भी कर सके। उन्होंने अपने जीवन का बहुमूल्य समय पद्रेश की जनता को समर्पित कर यह सिद्ध कर दिया है कि उनका जीवन केवल उनका नहीं है अपितु प्रदेश की जनता की नि: स्वार्थ सेवा के लिए समर्पित है। वे सही मायने में एक ऐसे जननेता हैं जिनके लिए जनता ही सब कुछ हैं। ऐसे सेवाभावी और लोकप्रिय जनसेवक बहुत कम होते हैं जिनके लिए जनता का विकास और जनता का साथ ही सबसे महत्वपूर्ण होता है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का अब तक का कार्यकाल इस बात का प्रमाण है कि यदि नेतृत्व ईमानदार, समर्पित और जनता की आकांक्षाओं से जुड़ा हो तो विकास की राह कठिन नहीं होगी।

हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलने का बीड़ा उठाया

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलने का बीड़ा उठाया है। उन्होंने प्रदेश के हर वर्ग की बुनियादी सुविधाओं और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पीएम आवास योजना, कृषक उन्नति योजना, नियद नेल्ला नार, अखरा निर्माण योजना जैसी योजनाओं का शुभारम्भ किया है और जनता के बीच अपनी एक अलग छवि निर्मित की है।

छत्तीसगढ़ राज्य में यह पहली बार हुआ है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में स्कूलों में एक विशेष अवसर पर न्योता भोजन का भी आयोजन किया जाता है। न्योता भोजन सामुदायिक भागीदारी पर आधारित एक ऐसा उपक्रम है जिसके माध्यम से स्कूल के बच्चों को समाज से जोड़ा जा सके एवं उनके भीतर समानता की भावना विकसित किया जा सके।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जनता के बीच और हर समुदाय के बीच एक ऐसा पुल बनाना जानते हैं जिससे सभी एक दूसरे से जुड़ सके और सभी प्रदेश के हित में अपनी-अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह भी कर सके। उन्होंने अपने जीवन का बहुमूल्य समय पद्रेश की जनता को समर्पित कर यह सिद्ध कर दिया है कि उनका जीवन केवल उनका नहीं है अपितु प्रदेश की जनता की निस्वार्थ सेवा के लिए समर्पित है। वे सही मायने में एक ऐसे जननेता हैं जिनके लिए जनता ही सब कुछ हैं। ऐसे सेवाभावी और लोकप्रिय जनसेवक बहुत कम होते हैं जिनके लिए जनता का विकास और जनता का साथ ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। यह सभी प्रदेशवासियों के लिए गौरवान्वित होने का विषय है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उनके अपने बीच के लोकप्रिय नेता हैं जिनके लिए प्रदेश की जनता की खुशहाली ही सर्वोपरि है

ईरान पर हमले से बढ़ी वैश्विक अनिश्चितता

ईरान पर इस्त्राइल-अमेरिका के हमले से पश्चिम एशिया की शांति और स्थिरता दांव पर लगी है. इस जंग पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं आश्वस्त तो करती हैं, पर देखने की बात यह है कि इनका कितना दबाव दोनों पक्षों पर पड़ता है और संयुक्त राष्ट्र इस पर क्या कदम उठाता है. भारत के लिए पश्चिम एशिया का पूरा इलाका बेहद महत्वपूर्ण है. भारत ने इस जंग पर चिंता तो जतायी ही है, ईरान पर हमले से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने इस्त्राइल में कहा था कि मध्य एशिया की स्थिरता और शांति से भारत के हित जुड़े हैं.

इस्त्राइल ने अमेरिका की मदद से शनिवार की सुबह ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई शहरों पर ताबड़तोड़ हमले कर जिस तरह उसके सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई को निशाना बनाया, उसके बाद ईरान समेत पूरे पश्चिम एशिया में अस्थिरता फैल गयी है. इस्त्राइल ने हमले की शुरुआत ही ईरान के खुफिया मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सुप्रीम लीडर खामेनेई और ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन को निशाना बनाकर की. खामेनेई के मारे जाने पर ईरान में 40 दिन के राजकीय शोक और सात दिन की छुट्टी घोषित की गयी है. ईरान ने अपने सुप्रीम लीडर की मौत का भीषण बदला लेने की बात भी कही है. खामेनेई को खत्म कर इस्त्राइल और अमेरिका फौरी तौर पर अपने उद्देश्य में सफल हुए हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य ईरान में सत्ता परिवर्तन करना है. पिछले साल ईरान की जनता जब सड़कों पर उतर गयी थी, तब अमेरिका ने उसका समर्थन किया था. ट्रंप प्रशासन ने तब कहा भी था कि अगर आंदोलनरत नागरिकों को निशाना बनाने की कोशिश की गयी, तो तेहरान को उसका अंजाम भुगतना पड़ सकता है. ईरान पर हमले के दौरान नेतन्याहू की यह टिप्पणी, कि ईरानियों को भाग्य बदलने का मौका मिलेगा, इस्त्राइल-अमेरिका के इसी उद्देश्य के बारे में बताती है.

> **ईरान पर यह हमला ओमान की मदद से ईरान और अमेरिका के बीच जिनेवा में परमाणु हथियारों को लेकर चली बातचीत के बेनतीजा रहने के दो दिन बाद हुआ है. वार्ता में बैलेस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट विवाद का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया था और ईरान इस पर समझौता करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं उसका कहना था कि बातचीत केवल परमाणु कार्यक्रम तक सीमित रहेगी, मिसाइल या क्षेत्रीय समूहों पर नहीं.**

ईरान पर यह हमला ओमान की मदद से ईरान और अमेरिका के बीच जिनेवा में परमाणु हथियारों को लेकर चली बातचीत के बेनतीजा रहने के दो दिन बाद हुआ है. वार्ता में बैलेस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट विवाद का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया था और ईरान इस पर समझौता करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है. उसका कहना था कि बातचीत केवल परमाणु कार्यक्रम तक सीमित रहेगी, मिसाइल या क्षेत्रीय समूहों पर नहीं. ईरान का यह भी मानना था कि पिछले साल जून में जब इस्त्राइल और अमेरिका ने ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमला किया था, तब ईरान की मिसाइलों ने उसकी रक्षा की थी. ईरानी अधिकारियों ने बार-बार यह कहा है कि मिसाइल कार्यक्रम पर कोई बात नहीं होगी. यह ईरान की रक्षात्मक क्षमता है और इसे छोड़ने का अर्थ खुद को कमजोर करना होगा. जबकि ट्रंप ने कहा है कि इस कार्रवाई का मकसद अमेरिका और उसके लोगों को खतरे से बचाना है. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले ही ईरान पर हमले की धमकी दी थी. अमेरिकी सेना ईरान को घेर चुकी थी.

हमले से पहले अमेरिका ने अपने नागरिकों से तुरंत इस्त्राइल छोड़ने के लिए कहा था. इस्त्राइली हमले के जवाब में ईरान ने भी पलटवार करते हुए मिसाइलें दागी हैं. उसने इस्त्राइल के अलावा कुवैत, कतर, बहरीन और सऊदी अरब में मौजूद

नेपाल में लोकतांत्रिक बदलाव का मतलब

बालेन शाह के नेतृत्व में नेपाल एक नये दौर में प्रवेश कर रहा है. आने वाले महीने ये बतायेंगे कि क्या उनकी पार्टी अपने व्यापक सुधार एजेंडे को ठोस नीति और शासन परिणामों में बदल सकती है. बालेन शाह एक आत्मविश्वासी, तकनीकी और राष्ट्रवादी पीढ़ी का चेहरा हैं, जो भारत के साथ 'विशेष संबंध' को समानता और 'नेपाल पहले' के दृष्टिकोण पर आधारित करने को प्राथमिकता देते हैं. भारत की चुनौती यह सुनिश्चित करने की होगी कि शाह की 'नेपाल फर्स्ट' नीति 'चीन फर्स्ट' में न बदल जाए. भारत को अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक और भौगोलिक भूमिका को प्रभावी ढंग से जोर देना होगा.

नेपाल के चुनाव में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) की ऐतिहासिक जीत हिमालय के राजनीतिक परिदृश्य में व्यापक लोकतांत्रिक बदलाव का संकेत देती है. आरएसपी की स्थापना 2022 में रवि लामिछाने द्वारा की गयी थी, इसके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बलेंद्र 'बालेन' शाह हैं. बालेन ने चुनाव अभियान के दौरान खुद को 'मधेश के पुत्र' के रूप में पेश किया था, और आरएसपी ने 'अब की बार बलेंद्र सरकार' टैगलाइन के साथ चुनाव अभियान शुरू किया था. पिछले साल जेन जी के आंदोलन ने नेपाल की राजनीति को पूरी तरह हिला दिया था. उस आंदोलन के कारण केपी शर्मा ओली की सरकार गिर गयी थी और देश में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ गयी थी. इस चुनाव में भ्रष्टाचार और सिस्टम में बदलाव, आर्थिक संकट, बढ़ती बेरोजगारी और शासन के प्रति असंतोष जैसे मुद्दे थे.

नेपाल की पारंपरिक राजनीतिक शक्तियों में सबसे प्रमुख नाम केपी शर्मा ओली की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल है. इसके अलावा पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' की नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी भी बड़ी ताकत मानी जाती है. लेकिन आरएसपी की यह जीत मतदाताओं द्वारा पारंपरिक स्थापित पार्टियों की पूरी तरह से अस्वीकृति का संकेत है. चुनाव में 1.89 करोड़ योग्य मतदाताओं की मजबूत भागीदारी देखी गयी, जिसमें 2022 से 9,15,000 से अधिक नये मतदाताओं की वृद्धि शामिल है, जो जेन जी के महत्वपूर्ण प्रभाव को दर्शाती है. मतदान नेपाल के सभी 77 जिलों में एक ही चरण में हुआ. जैसे ही आरएसपी ने प्रतिनिधि सभा में भारी बहुमत हासिल किया, ध्यान तेजी से उन महत्वाकांक्षी सुधारों की ओर बढ़ रहा है, जिन्हें पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में लागू करने का वादा किया है.

घरेलू स्तर पर पार्टी ने व्यापक राजनीतिक सुधारों की वकालत की है, जिसमें मतदाताओं द्वारा सीधे चुने गये प्रधानमंत्री और पूरी तरह से आनुपातिक संसदीय प्रणाली की शुरुआत शामिल है. आरएसपी की महत्वपूर्ण प्रतिबद्धताओं में से एक है सत्ता संभालने के तीन महीनों के भीतर संवैधानिक संशोधनों पर बहस शुरू करना. आरएसपी ने राज्य संचालन में संरचनात्मक बदलाव का भी प्रस्ताव रखा है, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि सांसद एक ही समय में मंत्री के रूप में कार्य न करें, और पार्टी का कहना है कि यह कदम कार्यपालिका के संसदीय निरीक्षण को मजबूत करेगा. घोषणा पत्र में 1990 में लोकतंत्र बहाल होने के बाद से सभी सार्वजनिक कार्यालयधारियों की संपत्ति की व्यापक जांच कराने का भी प्रस्ताव है. अवैध तरीके से प्राप्त संपत्ति को राष्ट्रीयकृत किया जायेगा.

आरएसपी के सुधार एजेंडा का एक प्रमुख हिस्सा संघीय सरकार के पुनर्गठन से संबंधित है. इसने 18 संघीय मंत्रालयों तक संख्या को सीमित रखने का वचन दिया है, जबकि 14 मंत्रालयों को विशेषज्ञ मंत्रियों द्वारा संचालित करने का प्रावधान है. इसके अतिरिक्त, आरएसपी सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को राष्ट्रीय रणनीतिक उद्योग घोषित करने की योजना बना रही है, जिससे नेपाल को डिजिटल सेवाओं के लिए एक क्षेत्रीय केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सके. पार्टी ने महत्वाकांक्षी ऊर्जा लक्ष्य निर्धारित कर अगले दशक में 30,000 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने का वचन दिया है. नेपाल में चुनाव के सफल और शांतिपूर्ण संचालन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'मैं नेपाल के लोगों और सरकार को हार्दिक बधाई देता हूं. यह देखकर खुशी होती है कि मेरी नेपाली बहनें और भाई अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का इतने ऊर्जा के साथ उपयोग कर रहे हैं. यह ऐतिहासिक उपलब्धि नेपाल की लोकतांत्रिक यात्रा के गर्व का क्षण है. एक करीबी मित्र और पड़ोसी के रूप में, भारत नेपाल के लोगों और उनकी नयी सरकार के साथ मिलकर साझा शांति, प्रगति और समृद्धि की नयी ऊंचाइयों को प्राप्त करने के अपने संकल्प में स्थिर बना हुआ है.'

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और विदेशी निवेश का मुख्य स्रोत है. दशकों से भारत की नेपाल नीति नेपाली कांग्रेस और सीपीएन-यूएमएल जैसी स्थापित पार्टियों के साथ स्थिर संबंधों पर आधारित है. बालेन शाह का उदय इस युग में बदलाव का संकेत देते हैं. बालेन शाह एक आत्मविश्वासी, तकनीकी और राष्ट्रवादी पीढ़ी का चेहरा हैं, जो भारत के साथ 'विशेष संबंध' को समानता और 'नेपाल पहले' के दृष्टिकोण पर आधारित करने को प्राथमिकता देते हैं. उनके पहले 'वृहत नेपाल' मानचित्र विवाद और काठमांडू में भारतीय फिल्मों पर उनकी अस्थायी रोक उनके जनवादी राष्ट्रवाद के शुरुआती संकेत हैं. संसद में दो-तिहाई बहुमत के साथ शाह को संवेदनशील मुद्दों, जैसे कि 1950 का शांति और मित्रता संधि और कालापानी-लिपुलेख सीमा विवाद पर यथार्थवादी रुख अपनाने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है.

राष्ट्रवादी रुख रखने के बावजूद, शाह की मूल अपील उनके घोषणापत्र में निहित है, जो 'विकास' पर केंद्रित है, और 12 लाख नौकरियां सृजित करने, जीडीपी को 100 अरब डॉलर तक बढ़ाने और शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार करने का वादा करता है. यह भारत की 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है. अगर भारत अपनी विकासात्मक सहायता को शाह की तकनीकी प्राथमिकताओं के साथ मिलाकर, खासकर जलविद्युत, डिजिटल कनेक्टिविटी और एकीकृत चेक-पॉइंट में काम कर कर सके, तो यह आर्थिक उपयोगिता पर आधारित नया साझेदार तैयार कर सकता है. आरएसपी ने नेपाल को 'बफर स्टेट' से 'सक्रिय सेतु' (वाइब्रेंट ब्रिज) में बदलने का संकल्प जताया है.

देश के प्रत्येक व्यक्ति को जनजातीय इतिहास को जानना चाहिए-चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति सूर्यकांत

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने नवा रायपुर में बने देश का पहला डिजिटल संग्रहालय का किया अवलोकन

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति श्री सूर्यकांत ने आज राजधानी नवा रायपुर के आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान में बने देश के पहले डिजिटल संग्रहालय का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ का यह जनजातीय संग्रहालय अद्वितीय है। उन्होंने कहा कि देश के प्रत्येक नागरिक को जनजातीय इतिहास और संस्कृति से वाकिफ होना चाहिए।

चीफ जस्टिस ने छत्तीसगढ़ के जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के अंदोलनों और शौर्य गाथाओं पर संग्रहालय में बने प्रत्येक गैलरी को निकट से देखा। उन्होंने कहा कि इस संग्रहालय में जनजातीय आंदोलनों की स्मृतियां लोगों को शोषण एवं अन्याय के खिलाफ एक जुट होने और उसका प्रतिकार करने के लिए प्रेरित करेंगी।

आदिमजाति विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणी बोरा ने जनजातीय संग्रहालय पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस श्री सूर्यकांत, जस्टिस श्री पी.एस.नरसिम्हा, जस्टिस श्री प्रशांत कुमार और हाईकोर्ट बिलासपुर के चीफ जस्टिस श्री रमेश सिन्हा, राजस्थान के चीफ जस्टिस श्री कल्पथी राजेंद्रन श्रीराम सहित अन्य न्यायाधीश गण का बीरनमाला से आत्मीय स्वागत करने के साथ ही उन्हें स्मृति स्वरूप जनजातीय जीवन पर आधारित भित्ती चित्र भेंट किया।

प्रमुख सचिव श्री बोरा ने जनजातीय संग्रहालय के अवलोकन के दौरान चीफ जस्टिस श्री सूर्यकांत सहित अन्य न्यायधीश गणों को जनजातीय विद्रोहों की पृष्ठिभूमि और जनजातीय नायकों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। श्री बोरा ने संग्रहालय के अलग-अलग गैलरियों में प्रदर्शित विद्रोहों को साल, साजा और महुआ के प्रतिकात्मक वृक्ष के पत्तों के जरिये समझाने का प्रयास किया गया है। संग्रहालय में बने यह वृक्ष उसी तरह से है जिस तरह से मोशन फिल्मों में एक वृद्ध व्यक्ति फिल्म की कहानी बताते है।

चीफ जस्टिस श्री सूर्यकांत ने जनजातीय संग्रहालय में प्रदर्शित भूमकाल विद्रोह के बारे में जानकर काफी प्रभावित हुए। यह विद्रोह बस्तर क्षेत्र के चित्रकोट के आस-पास वर्ष 1910 में हुआ था। यह विद्रोह 20 वर्षीय जननायक गुंडाधुर के नेतृत्व में, औपनिवेशिक वन नीतियों, जमींदारों के शोषण और बाहरी हस्तक्षेप के विरूद्ध था, जिसमें आदिवासियों ने पारंपरिक हथियारों से अंग्रेजों के खिलाफ किया था। चीफ जस्टिस ने संग्रहालय में शहीद वीर नारायण सिंह की तलवार सहित अन्य जनजातीय नायकों द्वारा विद्रोह के दौरान उपयोग में लाए गए अस्त्र-शस्त्र का भी अवलोकन किया।

चीफ जस्टिस ने गैलरी में स्थापित मां दंतेश्वरी का प्रतिकात्मक डिजिटल मंदिर से काफी प्रभावित हुए उन्होंने दो बार घंटी बजाकर मां दंतेश्वरी के दर्शन किया। उन्होंने आगामी समय बस्तर (दंतेवाड़ा) जाकर मां दंतेश्वरी की साक्षात दर्शन करने की इच्छा जाहिर की।

उल्लेखीनय है कि छत्तीसगढ़ राज्योत्सव रजत जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 01 नवबंर 2025 को इस भव्य डिजिटल संग्रहालय को लोगों को समर्पित किया था। तब से आगुन्तकों के लिए यह संग्रहालय आर्कषण एवं उत्साह का केंद्र बना हुआ है। जनसमुदाय में इस संग्रहालय के प्रति आकर्षण और लोकप्रियता को देखते हुए इसके द्वितीय चरण के विस्तार की कार्ययोजना तैयार की जा रही है।

गौरतलब है कि आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणी के मार्गदर्शन में जनजातीय संस्कृति एवं परंपराओं पर आधारित म्यूजियम तथा सहित वीर नारायण सिंह स्मारक सह जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी म्यूजियम का निर्माण तेजी के साथ पूरा हुआ है। मुख्य मंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देश पर निर्माण से उद्घाटन तक विभाग के अधिकारी-कर्मचारी श्री बोरा के नेतृत्व में बारीकी से एक-एक पहलुओं को परखा तब जाकर संग्रहालय का बुनियाद बनकर तैयार हुआ है। संग्रहालय का धरातल में आने से नई पीढ़ियों को अपने पुरखों की वीरता और साहस का याद दिलाता रहेगा। यह न केवल जनजातीय वर्गों के बल्कि सभी लोगों के प्रेरणापद है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को मिलीं जन-जन की शुभकामनाएं,

जन्मदिन पर मुख्यमंत्री निवास बना उल्लास का केंद्र

प्रोजेक्ट धड़कन, जिंदगी मुस्कुराएगी, दिव्य धुन बैंड और कलाकेंद्र के बच्चों संग मुख्यमंत्री ने बांटी खुशियांप्रोजेक्ट धड़कन, जिंदगी मुस्कुराएगी, दिव्य धुन बैंड और कलाकेंद्र के बच्चों संग मुख्यमंत्री ने बांटी खुशियांप्रोजेक्ट धड़कन, जिंदगी मुस्कुराएगी, दिव्य धुन बैंड और कलाकेंद्र के बच्चों संग मुख्यमंत्री ने बांटी खुशियांप्रोजेक्ट धड़कन, जिंदगी मुस्कुराएगी, दिव्य धुन बैंड और कलाकेंद्र के बच्चों संग मुख्यमंत्री ने बांटी खुशियांमुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के जन्मदिन पर राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास देर रात तक उल्लास और स्नेह के वातावरण से भरा रहा। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, उद्योगपतियों, समाजसेवियों और मीडिया प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएँ दीं। मुख्यमंत्री को जन्मदिवस के अवसर पर फलों से तौला गया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने सभी आगंतुकों से आत्मीयता से मुलाकात की और स्नेह, सम्मान और शुभकामनाओं के लिए कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आप सभी के प्रेम और सहयोग से मैं अभिभूत हूँ। छत्तीसगढ़ के उज्ज्वल भविष्य के लिए हम सभी को मिलकर कार्य करना है। आपका निरंतर समर्थन और आशीर्वाद इसी तरह बना रहे, यही मेरी कामना है।

प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने दी शुभकामनाएं

मुख्यमंत्री निवास में मंत्रीगण,विधायकों और जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री श्री साय को बधाई दी। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह,खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल,वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री लखन लाल देवांगन, वन मंत्री श्री केदार कश्यप,महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं दीं।

इसके साथ ही विधायकगण श्री धरमलाल कौशिक, श्री अजय चंद्राकर,श्री पुरंदर मिश्रा, श्री मोतीलाल साहू, गुरु खुशवंत साहेब, श्री दीपेश साहू और श्री ललित चन्द्राकर सहित विभिन्न आयोग एवं मंडल के अध्यक्षों, सदस्यों ने भी मुख्यमंत्री से भेंट कर जन्मदिन की बधाई दी।

प्रदेशभर से उमड़ा शुभकामनाओं का सैलाब

मुख्यमंत्री श्री साय को प्रदेश के उद्योगपतियों,व्यापारी संगठनों, खेल जगत के प्रतिनिधियों,समाजिक संगठन, दिव्यांग संगठन,अल्पसंख्यक समाज, समाजसेवियों, शिक्षाविदों और मीडिया जगत के वरिष्ठ जनों ने भी शुभकामनाएँ दीं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर सभी का आभार व्यक्त करते हुए प्रदेश के सर्वांगीण विकास और समृद्धि के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को आत्मनिर्भर और विकसित प्रदेश बनाने के लिए सरकार प्रत्येक वर्ग के हित में कार्य कर रही है, और यह प्रयास निरंतर जारी रहेगा।

मुख्यमंत्री ने प्रोजेक्ट धड़कन और जिंदगी मुस्कुराएगी के बच्चों संग बांटी खुशियां

जिला प्रशासन रायपुर एवं स्वास्थ्य विभाग की पहल प्रोजेक्ट धड़कन के तहत हृदय रोग की सर्जरी के बाद बच्चे पारुल, नमन शर्मा और हिमांशु ध्रुव और प्रोजेक्ट जिंदगी मुस्कुराएगी के तहत नाक की सर्जरी के बाद नन्ही प्रेमिन साहू ने भी अपने प्रिय मुख्यमंत्री से मिलकर उन्हें जन्मदिवस की बधाई दी। मुख्यमंत्री बड़ी ही आत्मीयता से इन बच्चों से मिले और उन्हें दुलारते हुए नन्हे नमन शर्मा को अपनी गोद में उठा लिया। मुख्यमंत्री ने छोटी सी उम्र में गंभीर बीमारियों का मुकाबला कर रहे बहादुर बच्चों का खूब हौसला बढ़ाया और बच्चों को गिफ्ट में प्रेरक किताबें भेंट की।

प्रोजेक्ट दिव्य धुन और कला केंद्र के बच्चों ने बांधा समां

मुख्यमंत्री के जन्मदिवस पर प्रोजेक्ट दिव्य धुन के तहत शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधित विद्यालय मठपुरैना के बच्चों के बच्चों ने गीतों की मधुर प्रस्तुति दी। बच्चों ने बार बार दिन ये आए, अंगना म भारत माता के चिरैया सहित जसजीत, करमा और देवार गीत से समां बांध दिया। मुख्यमंत्री श्री साय बहुत प्रेम से बच्चों से मिले और उनकी कला को सराहा। उन्होंने बच्चों को ट्रैक सूट, लोवर टीशर्ट और प्रोत्साहन राशि भेंट की।

कला केंद्र रायपुर के बच्चे भी अपने चहेते मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बधाई देने पहुंचे। कक्षा आठवीं के विद्यार्थी नन्हे आदित्य शर्मा ने अपने द्वारा बनाया मुख्यमंत्री का स्केच उन्हें भेंट किया। वायलिन वादक बच्चे आरीव झा और अमायरा अग्रवाल, तबला वादक योगेश सिंह सहित सभी बच्चों को मुख्यमंत्री ने खूब दुलारा और उन्हें उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।

जन्मदिन की बधाई देने सामाजिक संगठनों और नागरिकों का लगा तांता

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को उनके जन्मदिवस पर बधाई देने बड़ी संख्या में सामाजिक संगठन और नागरिकगण पहुंचे। महिला अधिवक्ताओं ने पगड़ी पहनाकर मुख्यमंत्री का सम्मान किया।

जरूरी है. रोहित ने खुद मिसाल पेश करते हुए विरोधी खेमे पर पहली गेंद से ही हल्ला बोलना शुरू कर दिया. रोहित-राहुल द्रविड़ की कमान में भारत ने 2024 में टी-20 विश्व कप जीता और यहीं से भारतीय टीम के स्वर्णकाल की शुरुआत हुई.

गौतम गंभीर के हेड कोच बनने के बाद भारतीय टीम ने 2026 के टी-20 विश्व कप की तैयारी शुरू कर दी. सूर्यकुमार यादव को टीम की कमान सौपी गयी और उन्हें सिर्फ टी-20 फॉर्मेट पर फोकस करने को कहा गया. ऐसे ही, फिटनेस की समस्या से जूझ रहे हार्दिक पंड्या टीम के लिए असरदार ऑलराउंडर साबित हुए. इसके अलावा टीम इंडिया ने ऐसी टीम की रचना शुरू कर दी, जो पहली गेंद से हल्ला बोले. रोहित शर्मा और विराट कोहली के टी-20 से रिटायरमेंट के बाद संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा को ओपनिंग की जिम्मेदारी दी गयी. ऐसे ही, टीम को साफ संदेश दे दिया गया कि पहले तीन पोजीशन के अलावा किसी को भी कभी भी वक्त के हिसाब से भेजा जा सकता है.

तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल और रिंकू सिंह को फ्लोटर की भूमिका दी गयी. टीम ने नाम को नहीं, फॉर्म को तवज्जो दी और इसलिए शुभमन गिल की जगह ईशान किशन को टीम में शामिल कर लिया. नतीजा सामने था. भारतीय टीम ने 200 के स्कोर को न्यू नॉर्मल बना लिया. जब आप 200 से अधिक का स्कोर बनाते हैं, तो टॉस और ओस मैच का फैसला तय नहीं करते. इसके अलावा टीम इंडिया ने ऑलराउंडर को टीम में तवज्जो दी. इसलिए विकेट के हिसाब से कभी कुलदीप यादव, तो कभी अर्शदीप बाहर बैठे और अक्षर, हर्षित, शिवम और वाशिंगटन सुंदर को मौका मिला.

इस बीच भारतीय टीम के पास जसप्रीत बुमराह के रूप में नायाब हीरा है. बुमराह खुद को क्रिकेट में किसी भी दौर के महानतम गेंदबाजों में से एक साबित कर चुके हैं. वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व महान गेंदबाज उन्हें तेज गेंदबाजी की गुर का दिग्गज मान चुके हैं. टेस्ट क्रिकेट और एकदिवसीय क्रिकेट में तो कोई बुमराह के गेंदबाजी स्पेल से बचकर निकल भी सकता है, लेकिन टी-20 क्रिकेट में उनके चार ओवर डेथ वारंट के समान होते हैं. भारतीय टीम प्रबंधन और चयनकर्ता ने उनके वर्कलोड को भी बेहतरीन तरीके से संभाला है.

हर विश्व कप की जीत एक नायक लेकर आता है. इस बार के विश्व कप की जीत के नायक संजू सैमसन हैं. संजू सैमसन के पास हुनर है, इसका अंदाजा हर किसी को बीते दस साल से था. वह हुनर अब विश्वविजेता टीम को अपने अंजाम तक पहुंचाने में सूत्रधार बनेगा, यह टी-20 विश्व कप की तीन यादगार पारियों से साबित हुआ. संजू सैमसन की इन तीन पारियों ने भारत को ट्रॉफी तक पहुंचाया. लेकिन संजू और टीम इंडिया का पड़ाव अभी खत्म नहीं हुआ है. अभी एकदिवसीय विश्व कप और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतनी है. तभी सही मायने में टीम इंडिया का स्वर्णकाल होगा.

गौतम गंभीर ने पहले खिलाड़ी फिर कोच बनकर जीती वर्ल्ड कप ट्रॉफी

भारत ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी को एक बार फिर से उठाकर क्रिकेट जगत के सिंहासन पर अपना कब्जा जमा लिया है। जो लोग चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की जीत को तुक्का कह रहे थे आज उनकी खामोशी ही गौतम गंभीर की सबसे बड़ी सफलता है। जहां एक तरफ टेस्ट फॉर्मेट में खराब प्रदर्शन के चलते गंभीर की लगातार आलोचना हो रही है वहीं गंभीर के अंडर टीम इंडिया आईसीसी टूर्नामेंट्स में कमाल का प्रदर्शन कर रही है और पहली बार टी20 वर्ल्ड कप के खिताब को डिफेंड करना उसका सबसे बड़ा सबूत है।

2025 में चैंपियंस ट्रॉफी और अब 2026 में टी20 वर्ल्ड कप यह बैक-टू-बैक जीत साबित करती है कि यह कोई तुक्का नहीं बल्कि एक मास्टरमाइंड की प्लानिंग है। गंभीर की कोचिंग में टीम इंडिया अब घातक क्रिकेट खेलती है और दुनियाभर की टीमें भारत के सामने बेबस नजर आती हैं। सेमीफाइनल और फाइनल जैसे हाईवोल्टेज मुकाबलों में 250 से ज्यादा रन बनना इस बात का प्रमाण है कि गंभीर के राज में टीम में डर नाम का शब्द घुसता ही नहीं।

आलोचकों के मुंह पर जड़ा ताला

जिन लोगों ने गंभीर की काबिलियत पर सवाल उठाए थे आज उन्हें अपनी राय बदलने पर मजबूर होना पड़ा है। गौतम गंभीर ने भारतीय ड्रेसिंग रूम में जो विनिंग मेंटालिटी भरी है उसका नतीजा आज पूरी दुनिया के सामने है। अब टीम इंडिया सिर्फ मैच नहीं जीतती बल्कि मैदान पर अपना दबदबा बनाती है। न्यूजीलैंड की टीम सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 13 ओवर से पहले 170 रन चेज करके आई थी। लेकिन गंभीर के सूरमाओं के सामने कीवी गेंदबाज और बल्लेबाज पहले ओवर से ही बैकफुट पर रहे।

संजू सैमसन को बैक करना गजब का फैसला

इतना ही नहीं, गंभीर ने जिस तरह से टीम इंडिया के फेल खिलाड़ियों को बैक किया वो भी एक काबिल लीडर की पहचान है। सैमसन न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में फ्लॉप रहे थे तो उन्हें टी20 वर्ल्ड कप के शुरुआती मैचों में बाहर कर दिया गया। इसके बाद उन्हें टीम में वापस लाया गया और वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन गए। यहां तक कि अभिषेक शर्मा इस पूरे टूर्नामेंट में नहीं चल पाए लेकिन गंभीर ने उनको फाइनल तक टीम में लगातार मौके दिए। गंभीर अपने फैसलों पर हमेशा खड़े रहते हैं फिर चाहे बाहर कुछ भी माहौल चल रहा हो।

टी-20 विश्व कप में भारतीय क्रिकेट का स्वर्णकाल

टीम इंडिया ने 2024 के टी-20 विश्व कप और 2026 टी-20 विश्व कप के बीच टी-20 की आठ शृंखलाओं में जीत हासिल की, जिनमें से सात जीत सूर्यकुमार यादव की कप्तानी और गौतम गंभीर के हेड कोच के दौर में मिली. इस आधार पर यह निस्संदेह सफेद बॉल फॉर्मेट में भारतीय क्रिकेट का स्वर्णकाल है . क्रिकेट के पंडितों को भारतीय क्रिकेट का पराक्रम किसी दौर में वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया की टीमों की धमक की याद दिलाता है.

किसी भी खेल में विश्व कप की ट्रॉफी जीतना एक ऐतिहासिक लम्हा होता है. यह ऐतिहासिक पल तब यादगार स्वर्णिम काल बन जाता है, जब ट्रॉफी की जीत एक आदत बन जाती है. सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय क्रिकेट टीम के लिए अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बीते रविवार की रात उस स्वर्णिम काल का ऐलान था. कपिल देव के नेतृत्व में 1983 में और महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में 2011 में भारत 50 ओवर के विश्व कप का चैंपियन बना. फिर धोनी की ही कप्तानी में भारत 2007 के टी-20 विश्व कप, फिर रोहित शर्मा की कप्तानी में 2024 में टी-20 विश्व कप का विजेता बना.

वर्ष 2023 के विश्व कप में भारत ने फाइनल को छोड़ अपने सभी मैच जीते थे. जबकि 2024 के टी-20 विश्व कप में अपने सभी मैच जीतकर भारत विश्वविजेता बना था. ऐसे ही, 2025 में सभी टीमों को हराकर भारत चैंपियंस ट्रॉफी विजेता बना. टीम इंडिया ने 2024 के टी-20 विश्व कप और 2026 टी-20 विश्व कप के बीच टी-20 की आठ शृंखलाओं में जीत हासिल की, जिनमें से सात जीत सूर्यकुमार यादव की कप्तानी और गौतम गंभीर के हेड कोच के दौर में मिली. इस आधार पर यह निस्संदेह सफेद बॉल फॉर्मेट में भारतीय क्रिकेट का स्वर्णकाल है . क्रिकेट के पंडितों को भारतीय क्रिकेट का पराक्रम किसी दौर में वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया की टीमों की धमक की याद दिलाता है.

यह स्वर्णिम दौर कब और कहां से आया? महेंद्र सिंह धोनी के बाद विराट कोहली ने टीम इंडिया की कमान संभाली. आइपीएल के शुरू होने से भारतीय क्रिकेट के टैलेंट पूल में इजाफा हुआ. विराट कोहली ने टीम को आक्रामकता, ऊर्जा और फिटनेस का मूलमंत्र दिया. इसने टीम को दो देशों के बीच सीरीज में तो जीत दिलानी शुरू कर दी, पर टीम का अभियान विश्व कप में सेमीफाइनल में जाकर रुक जाता था. फिर रोहित शर्मा टीम के सेनापति बने. उन्हें यह बात समझ में आ गयी थी कि विश्वविजेता बनने के लिए निडरता और पहली गेंद से आक्रामक रवैया

माँ का आशीर्वाद और अपार जनस्नेह

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का 62वाँ जन्मदिवस उनके गृहग्राम बगिया में अत्यंत उत्साह, आत्मीयता और पारिवारिक स्नेह के वातावरण में धूमधाम से मनाया गया। मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने गृहग्राम बगिया स्थित अपने घर पहुंचते ही सबसे पहले अपनी माता श्रीमती जसमनी देवी के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया।

मुख्यमंत्री श्री साय के जन्मदिवस पर उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं देने वालों का दिनभर तांता लगा रहा।जनप्रतिनिधियों, अधिकारी-कर्मचारियों तथा बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री को जन्मदिवस की शुभकामनाएं देते हुए उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना की। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर सभी के स्नेह, शुभकामनाओं और आत्मीय स्वागत के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनस्नेह ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने अपने जन्मदिवस को विशेष और यादगार बनाने के लिए सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया।

इस विशेष अवसर पर बगिया स्थित श्री राम सदन में सत्यनारायण व्रत कथा श्रवण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय, उनकी माताजी श्रीमती जसमनी देवी, धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या साय तथा परिवार के अन्य सदस्यों ने पूरे श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ व्रत कथा का श्रवण किया तथा ईश्वर से प्रदेश की सुख-समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के आगमन से पूर्व ही उनके गृहग्राम बगिया स्थित गृहनिवास में उनसे मिलने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी।जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं आम नागरिकों में मुख्यमंत्री से भेंट करने और उन्हें शुभकामनाएं देने को लेकर विशेष उत्साह और उत्सुकता देखने को मिली।

इस अवसर पर विधायक श्रीमती गोमती साय एवं श्रीमती रायमुनी भगत, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री सालिक साय, जिला पंचायत सदस्य श्री कृष्ण कुमार राय सहित जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के सदस्यगण, पंचायत प्रतिनिधि, नगरीय निकायों के प्रतिनिधिगण, जनप्रतिनिधि, कमिश्नर श्री नरेंद्र दुग्गा, आईजी श्री दीपक कुमार झा, कलेक्टर श्री रोहित व्यास, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उम्मेद सिंह तथा अन्य अधिकारियों एवं गणमान्य नागरिकों ने मुख्यमंत्री से भेंट कर उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

क्रिकेट में जिले का नाम रोशन कर चुकी छात्राओं को मुख्यमंत्री ने प्रदान की क्रिकेट किट

क्रिकेट की दुनिया में जिले का नाम रोशन करने वाली शासकीय प्री-मैट्रिक कन्या छात्रावास, इचकेला की प्रतिभाशाली छात्राओं को मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने प्रोत्साहित करते हुए 15 क्रिकेट किट प्रदान किया। छात्रावास की इन छात्राओं ने अपने उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन के दम पर राष्ट्रीय स्तर पर भी जिले को गौरवान्वित किया है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी छात्राओं को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आप इसी लगन, अनुशासन और मेहनत के साथ निरंतर आगे बढ़ती रहें तथा अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से राज्य और देश का नाम रोशन करें।

पारंपरिक परिधान में आए पहाड़ी कोरवा समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री को दी जन्मदिवस की बधाई

बगीचा से आए विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय पहाड़ी कोरवा समाज के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से सौजन्य भेंट कर उन्हें जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर पहाड़ी कोरवा समाज के सदस्य अपने पारम्परिक वेशभूषा एवं तीर-धनुष के साथ उपस्थित हुए, जिससे उनकी समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा की झलक दिखाई दी।मुख्यमंत्री श्री साय ने उनसे आत्मीय संवाद करते हुए उनके क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी ली। इस पर पहाड़ी कोरवा समाज के प्रतिनिधियों ने बताया कि वर्तमान में उनके क्षेत्रों में तेजी से विकास कार्य संचालित हो रहे हैं तथा प्रधानमंत्री जनमन योजना के माध्यम से उनके गांवों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि इस योजना से उनके जीवन स्तर में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है और उनके क्षेत्रों की तस्वीर बदल रही है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने उनकी बातों को गंभीरता से सुना और आश्वस्त किया कि विशेष पिछड़ी जनजातियों के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रतिबद्ध है।

बच्चों के चेहरों की मुस्कान बना मुख्यमंत्री साय के जन्मदिन का सबसे बड़ा उपहार

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने अपने 62वें जन्मदिवस को जशपुर के बगिया स्थित बालक आश्रम के बच्चों के बीच जिस आत्मीयता और स्नेह के साथ मनाया, उसने इस दिन को बच्चों के जीवन की एक अविस्मरणीय स्मृति बना दिया। जैसे ही मुख्यमंत्री आश्रम परिसर पहुँचे, बच्चों के चेहरों पर खुशी की चमक दौड़ गई। वे दौड़कर उनके पास आए और कुछ ही क्षणों में पूरा वातावरण एक पारिवारिक मिलन जैसा हो गया। उस पल मुख्यमंत्री किसी पद पर आसीन व्यक्ति नहीं, बल्कि बच्चों के अपने स्नेही अभिभावक की तरह उनके बीच दिखाई दे रहे थे। मुख्यमंत्री श्री साय ने बच्चों के साथ केक काटा और उनके साथ बैठकर बातें कीं। उन्होंने बच्चों के नाम पूछे, पढ़ाई के बारे में जाना, उनके सपनों को सुना और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। जब मुख्यमंत्री बच्चों से बात कर रहे थे, तब उनके चेहरे पर झलकता स्नेह और अपनत्व बच्चों के मन में गहरा विश्वास जगा रहा था। बच्चे भी पूरी सहजता से उनसे बातें करते हुए खुशी से चहकते रहे।

महिला सशक्तिकरण के नवयुग की ओर अग्रसर छत्तीसगढ़

डॉ. दानेश्वरी संभाकर
उप संचालक, जनसंपर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दौर से गुजर रहा है। मातृशक्ति के सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राज्य सरकार ने इस वर्ष को 'महतारी गौरव वर्ष' के रूप में मनाने की घोषणा की है। यह पहल केवल एक औपचारिक घोषणा नहीं है, बल्कि महिलाओं को राज्य की विकास यात्रा के केंद्र में स्थापित करने का सशक्त संकल्प है।

विश्वास से निर्माण और अब गौरव की ओर

मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने कार्यकाल के पहले वर्ष को 'विश्वास वर्ष' के रूप में शासन-प्रशासन और जनता के बीच भरोसे की पुनर्स्थापना को समर्पित किया। इसके बाद दूसरे वर्ष को भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में 'अटल निर्माण वर्ष' के रूप में मनाते हुए अधोसंरचना विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं को नई गति दी गई। अब तीसरा वर्ष 'महतारी गौरव वर्ष' के रूप में माताओं और बहनों को समर्पित किया गया है, जिसमें राज्य की अधिकांश योजनाओं का केंद्रबिंदु महिलाएं होंगी। यह क्रम सरकार की संवेदनशील और समावेशी विकास की सोच को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।

महतारी वंदन योजना - आत्मसम्मान और आर्थिक सुरक्षा का आधार

छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी वंदन योजना आज महिला सशक्तिकरण का मजबूत स्तंभ बन चुकी है। इस योजना के तहत प्रदेश की लगभग 70 लाख विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपये की सहायता सीधे उनके बैंक खातों में प्रदान की जा रही है। अब तक 16 हजार 237 करोड़ रुपये से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से महिलाओं को दी जा चुकी है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के दिन 25 वीं किस्त के रूप में 68 लाख से अधिक महिलाओं को 641 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई।यह नियमित आर्थिक सहयोग महिलाओं के आत्मविश्वास को बढ़ाने के साथ ही उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बना रहा है। कई महिलाएं इस राशि को केवल घरेलू खर्च तक सीमित न रखकर स्वरोजगार और छोटे व्यवसायों में निवेश कर रही हैं।

संघर्ष से स्वावलंबन तक - रोहनी पटेल की प्रेरक कहानी

बालोद जिले के ग्राम खैरडीह की श्रीमती रोहनी पटेल इसका एक प्रेरणादायक उदाहरण हैं। पति की असमय मृत्यु के बाद परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई थी। घर में वृद्ध सास की देखभाल और कॉलेज में पढ़ रहे दो बच्चों की पढ़ाई की चिंता उनके लिए बड़ी चुनौती थी।ऐसे कठिन समय में महतारी वंदन योजना उनके लिए उम्मीद की किरण बनकर आई। योजना से मिलने वाली राशि को उन्होंने सावधानीपूर्वक बचत कर अपने खेत में सब्जी उत्पादन का कार्य शुरू किया। बीज, खाद और कृषि सामग्री की व्यवस्था कर उन्होंने पूरी मेहनत से खेती की।

आज श्रीमती रोहनी पटेल अपने खेत में उगाई गई ताजी सब्जियों को स्थानीय बाजारों में बेचकर नियमित आय अर्जित कर रही हैं। इस आय से वे अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा कर रही हैं और बच्चों की पढ़ाई भी निर्बाध रूप से जारी है। उनका यह प्रयास गांव की अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा बन चुका है।

बिहान से बदली जिंदगी - 'लखपति दीदी' बनीं श्रीमती माहेश्वरी यादव

बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के ग्राम कोरदा की श्रीमती माहेश्वरी यादव भी महिला सशक्तिकरण की एक प्रेरक मिसाल हैं। पहले उनका जीवन सामान्य गृहिणी की तरह घर-परिवार की जिम्मेदारियों तक सीमित था। लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन 'बिहान' से जुड़ने के बाद उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन आया।

समूह के सहयोग और परिवार के समर्थन से उन्होंने गांव में एक छोटी किराना दुकान शुरू की। अपनी मेहनत और बेहतर प्रबंधन के बल पर यह दुकान धीरे-धीरे गांव में भरोसेमंद केंद्र बन गई। आज इस दुकान से उन्हें प्रतिवर्ष लगभग 1 से 1.5 लाख रुपये की आय हो रही है और वे 'लखपति दीदी' बन चुकी हैं। इससे उनके बच्चों की शिक्षा और परिवार की आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

आधुनिक तकनीक से नई पहचान - 'ड्रोन दीदी' सुश्री सीमा वर्मा

बिलासपुर जिले के मस्तूरी क्षेत्र की सुश्री

सीमा वर्मा ने भी यह साबित किया है कि अवसर और प्रशिक्षण मिलने पर महिलाएं आधुनिक तकनीक के क्षेत्र में भी नई पहचान बना सकती हैं।

स्व-सहायता समूह से जुड़ने के बाद उन्होंने पहले मशरूम उत्पादन का कार्य शुरू किया और बाद में ड्रोन संचालन का प्रशिक्षण प्राप्त किया। शासन की सहायता से उन्हें ड्रोन सेट, जनरेटर और ई-वाहन उपलब्ध कराया गया।

आज सीमा वर्मा किसानों के खेतों में ड्रोन के माध्यम से कीटनाशक छिड़काव कर रही हैं और इस कार्य से उन्हें सम्मानजनक आय प्राप्त हो रही है। गांव में लोग उन्हें स्नेहपूर्वक 'ड्रोन दीदी' के नाम से जानते हैं।

बजट में महिला कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता

राज्य सरकार ने महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए 8 हजार 245 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है।

आंगनबाड़ी एवं पोषण योजनाओं के लिए 2 हजार 320 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 120 करोड़ रुपये, मिशन वात्सल्य के लिए 80 करोड़ रुपये तथा रानी दुर्गावती योजना के लिए 15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

इसके अतिरिक्त 750 नए आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए 42 करोड़ रुपये और 250 महतारी सदनों के निर्माण के लिए 75 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। यह बजटीय प्रावधान महिलाओं और बच्चों के समग्र विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

सुरक्षा, स्वास्थ्य और गरिमा की सुदृढ़ व्यवस्था

महिला सुरक्षा के क्षेत्र में भी राज्य ने प्रभावी तंत्र विकसित किया है। वन स्टॉप सेंटर, 181 महिला हेल्पलाइन और डायल 112 के माध्यम से संकट की स्थिति में त्वरित सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। सुखद सहारा योजना के अंतर्गत 2 लाख 18 हजार से अधिक विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।

स्वावलंबन से नेतृत्व तक

प्रदेश में 42 हजार से अधिक महिला स्व-सहायता समूहों को रियायती ऋण प्रदान कर आर्थिक रूप से सशक्त बनाया गया है। रेडी-टू-ईट कार्य महिला समूहों को सौंपे जाने से उन्हें स्थायी आय का स्रोत मिला है। इसके साथ ही डिजिटल सखी, दीदी ई-रिक्शा, सिलाई मशीन सहायता, मिनीमाता महतारी जतन योजना और लखपति दीदी जैसी पहलें महिलाओं को नए आजीविका अवसर प्रदान कर रही हैं।

महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के अनुसार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें सुरक्षित तथा सम्मानजनक वातावरण प्रदान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

विकसित छत्तीसगढ़ की सशक्त आधारशिला

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य के अनुरूप 'छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047' के माध्यम से राज्य को समावेशी विकास की दिशा में आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसमें महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को अनिवार्य तत्व माना गया है।

'महतारी गौरव वर्ष' केवल एक प्रशासनिक पहल नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना का व्यापक अभियान है। यह वर्ष छत्तीसगढ़ में मातृशक्ति के सम्मान, आत्मविश्वास और नेतृत्व को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का संकल्प लेकर आया है। आज प्रदेश की महिलाएं आत्मनिर्भरता, नवाचार और नेतृत्व के साथ विकास की नई कहानी लिख रही हैं। यही सशक्त मातृशक्ति विकसित और समृद्ध छत्तीसगढ़ की सबसे मजबूत आधारशिला बनेगी।